सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 132, नई दिल्ली । मंगलवार, 23 जुलाई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा।

03 पेपर लीक 2500 करोड की इंडस्ट्रीज,बेवफा NTA
06 नए बजट से मध्यम वर्ग की उम्मीदें
08 ज़िला कलेक्टर ने किया ज़िले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक

क्या परिवहन विभाग के तकनीकी अधिकारियों की तरह अब दिल्ली से कंप्यूटराइज्ड वाहन जांच भी गायब होने वाली है?

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारियों और प्रशासन द्वारा परिवहन विभाग के आला अधिकारी के कार्यों को नजरंदाज करने की कार्यशैली से दिल्ली परिवहन विभाग में तकनीकी अधिकारियों द्वारा वीआरएस लिया जा रहा है और विभाग नए तकनीकी अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की जगह बचे हुए तकनीकी अधिकारियों को गैर तकनीकी पदो पर और गैर तकनीकी अधिकारियों को घोषित तकनीकी पदो पर विराजमान कर के अपनी इच्छा के कार्यों को पूरा करने में लगे हैं। संख्यिकी अधिकारी की नियुक्ति मुख्य मोटर वाहन कार्यालय में करके यह सिद्ध कर दिया की आला अधिकारियों को जनता की सुरक्षा नही सिर्फ राजस्व में इज़ाफा करवाना है और इसी तर्ज पर राज्य परिवहन की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण शाखा एसटीए से तो पूर्ण रूप से तकनीकी अधिकारियों को हटा कर गैर तकनीकी अधिकारी नियुक्त कर लिए। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें **दिल्ली में वाहन जांच के लिए दो शाखाए है पहली बुराड़ी और दूसरी झूलझूली।** बुराड़ी शाखा से ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड वाहन जांच बहुत पहले बंद हो गई और अब आला अधिकारी की कार्यशैली के रहते शायद जल्द ही झूलझूली ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड वाहन जांच बंद हो सकती है। **आख़िर दिल्ली की जनता को असुरक्षित क्यों करना चाहते हैं परिवहन विभाग के आला अधिकारी, बड़ा सवाल ? और उससे भी बड़ा सवाल उपराज्यपाल और मुख्य सचिव सब कुछ जानते और देखते हुए भी क्यों चुप हैं ?** आपकों हम पहले ही बता चुके हैं कि **इन्हीं आला अधिकारियों के कारण दिल्ली में सफर करने वाली महिलाओं को गृह सचिव भारत सरकार द्वारा गठित कमेटी और उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा दिए गए आदेशों/ दिशा निर्देशों वाली सार्वजनिक सवारी वाहनों में सुरक्षा नही मिल पा रही हैं या यह भी खुले शब्दों में कहा जा सकता हैं की यह देने नही दे रहे।**

डीटीसी के लोगो को लगाकर दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग की मिलीभगत से सड़कों पर चलाई जा रही ईलैक्ट्रिक बस मैट्रो पिलर से भिड़ी 1 की मौत, 23 घायल

परिवहन विशेष। एसडी सेठी। दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित मैट्रो के पिलर से डीटीसी की ईलैक्ट्रिक बस जा टकराई। इस बस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई, और करीब 23 से ज्यादा अन्य लोग घायल हो गए है। घायलों में एक की हालत गंभीर है उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। प्रात जानकारी के मुताबिक रोहिणी डिपो की रूट नंबर 939 की बस जो मंगोल पुरी से आनंद विहार की और जा रही थी।बस में सिटिंग सवारियां मौजूद थी। अचानक ड्राइवर का बस से नियंत्रण खो बैठा और मैट्रो पिलर से जबरदस्त तरीके से टकरा गई। ड्राइवर साईड से बस टकराने से बस का अगला भाग बुरी तरह से टूट गया है। ड्राइवर को ज्यादा चोटे आई है। पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक घायलों का पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। और आगे की कार्रवाई जारी है।

रिंग रोड पर पंजाबी बाग गोल चक्कर से प्रेमबाड़ी पुल के बीच रोड स्ट्रेच का अपग्रेडेशन व सुदृढ़ीकरण करवायेगी केजरीवाल सरकार

सुषमा रानी

नईदिल्ली। दिल्ली की सड़कों को यात्रियों के लिए सुंदर और सुरक्षित बनाना केजरीवाल सरकार की प्राथमिकता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार का लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मिशन मोड पर काम कर रहा है। इस दिशा में हाल ही में, पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में रिंग रोड पर प्रेमबाड़ी पुल से पंजाबी बाग़ गोल चक्कर तक की सड़क के अपग्रडेशन और सुदृढ़ीकरण को मंज़ूरी दी। बता है कि, ये सड़क रिंग रोड का महत्वपूर्ण स्ट्रेच है और रोज़ाना लाखों यात्री इनका उपयोग करते हैं।

परियोजना को मंजूरी देते हुए, उन्होंने कहा, "केजरीवाल सरकार का विज़न अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए शहर में एक वर्ल्ड क्लास और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क स्थापित करने पर है। इस दिशा में सरकार रिंग रोड जो दिल्ली में यातायात के लाइफ-लाइन की तरह है, शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती है और लाखों निवासियों के दैनिक आवागमन को सुविधाजनक बनाती है।

उन्होंने कहा कि, इसके तहत उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में रिंग रोड के प्रमुख रोड स्ट्रेच पर प्रेमबाड़ी पुल से पंजाबी बाग़ गोल चक्कर के सड़क का अपग्रेडेशन और सुदृढ़ीकरण करवाया जाएगा। ये पहल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विभिन्न क्षेत्रों की समग्र कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए दिल्ली के लोगों को सड़कों पर चलने के बेहतर अनुभव देने के विज़न का हिस्सा है।

बता दें कि रोज़ाना इस सड़क पर लाखों लोग आवाजाही करते है। ऐसे में भारी ट्रैफ़िक के कारण सड़क की ऊपरी सतह पर कई जगह दरार देखे गये है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी ने एक्सपर्ट्स की सहायता से सड़क का निरीक्षण किया है और पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जल्द से जल्द इसके सुदृढ़ीकरण के निर्देश दिये है।

उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली के लोगों से वादा है- राजधानी की सड़कों को वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की सड़कों में तब्दील करेंगे और उनके नेतृत्व में दिल्ली की सड़कों को को बेहतर बनाने के लिए सरकार 'मिशन मोड' में काम कर रही है। परियोजना को मंज़ूरी देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि,सुदृढ़ीकरण के दौरान सेफ्टी-सिक्योरिटी व क्वालिटी के सभी मानकों का प्रतिबद्धता से पालन हो और आवाजाही करने वालों को समस्या का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि, चाहे जितनी बाधाएँ आए लेकिन जबतक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, तबतक दिल्लीवालों के काम नहीं रुकेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्माण के दौरान यात्रियों को कोई असुविधा न हो और निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के सभी मानकों का पालन किया जाए।

दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन रास्तों से गुजरेंगे कांवड़िये

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली यातायात पुलिस ने कांवड़ियों और सड़क का उपयोग करने वालों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह भी दी है। कांवड़ियों के आवागमन की इस अवधि के दौरान ट्रैफिक उल्लंघन की जांच मौके पर ही चालान द्वारा की जाएगी। साथ ही उल्लंघन की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की जाएगी जिसके बाद चालान की कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और यातायात पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा, सुविधा के साथ ही यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं।

इस साल करीब 15 से 20 लाख कावड़ियों की आवाजाही का अनुमान लगाया गया है। आसपास के राज्यों से व दिल्ली से गंगोत्री धाम व हरिद्वार तक कांवड़ियों की आवाजाही होगी। काफी कांवड़िये दिल्ली होते हुए हरियाणा व राजस्थान भी जाएंगे।

कश्मीरी गेट के समीप तेज धूप व तपिश से पसीने में तरबतर होने के बावजूद भक्ती में लीन कदम बढ़ाते जाता कांवड़िया।

इस संख्या आधार पर दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी का पूरा मार्ग निर्धारित किया है। जिससे यातायात कम से कम प्रभावित हो और लोगों को असुविधा न हो। यह मार्ग निर्धारण आज से लागू हो जाएगा तथा दो अगस्त तक लागू रहेगा।

श्रद्धालु कांवड़ियों के लिए तय मार्ग...

अप्सरा बॉर्डर-शाहदरा फ्लाईओवर-सीलमपुर टी प्वाइंट-आइएसबीटी फ्लाईओवर, बुलेवार्ड रोड-रानी झांसी रोड-फैज रोड-अपर रिज रोड-धौला कुआं-एनएच-8 और हरियाणा के लिए रजोकरी बॉर्डर से बाहर निकलेंगे।

भोपुरा बॉर्डर-वजीराबाद रोड-लोनी फ्लाईओवर-गोकुलपुरी टी प्वाइंट-66 फुटा रोड-सीलमपुर -टी प्वाइंट-एनएच-एक और आगे नए आइएसबीटी ब्रिज की ओर निकलेंगे।

यूपी से लोनी बॉर्डर से लोनी फ्लाईओवर तक प्रवेश व निकास या यूपी से सोनिया विहार बॉर्डर-पुस्ता रोड-खजूरी फ्लाईओवर- वजीराबाद रोड से प्रवेश व निकास तक।

भोपुरा बॉर्डर-वजीराबाद रोड-वजीराबाद ब्रिज-बाहरी रिंग रोड-मुकरबा चौक-एनएच-एक और सिंघू बॉर्डर या मुकरबा चौक से निकास व प्रवेश-एनएच-एक, बवाना रोड और औचंदी बॉर्डर या मधुबन चौक-पीरागढ़ी से निकास व प्रवेश और निकास व प्रवेश टिकरी बॉर्डर से हरियाणा के लिए।

महाराजपुर बॉर्डर, रोड नंबर 56, गाजीपुर बॉर्डर-एनएच 24-रिंग रोड-मथुरा रोड और हरियाणा के लिए बदरपुर बॉर्डर से निकास तक।

न्यू रोहतक रोड (कमल टी -प्वाइंट से टिकरी बॉर्डर से जखीरा से लेकर नजफगढ़ तक।

रोहतक रोड जखीरा से मादीपुर से पीरागढ़ी चौक से नांगलोई चौक से मुंडका से टिकरी बॉर्डर पर।

नजफगढ़ रोड-जखीरा से उत्तम नगर तक, नजफगढ़ फिरनी रोड से झाड़ौदा बॉर्डर तक।

ऑउटर रिंग रोड-मधुबन चौक से पीरागढ़ी चौक से केशोपुर मंडी से डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी तक।

देव प्रकाश शास्त्री मार्ग-रतनपुरी चौक से लोहा मंडी तक।

इन जगहों पर वाहनों की आवाजाही...

आमतौर पर नजफगढ़ फिरनी, रोहतक रोड, पंखा रोड, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नांगलोई-नजफगढ़ रोड, आउटर रिंग रोड, रानी झांसी रोड पर बर्फखाना चौक से फायर स्टेशन, बुलेवार्ड रोड और आजाद मार्केट चौक, गोकुल पुरी फ्लाईओवर, 66 फुटा रोड, मौजपुर चौक, बदरपुर टी पाइंट, मथुरा रोड पर यातायात ज्यादा होता है।

इसी तरह, एनएच-आठ पर धौला कुआं मेट्रो स्टेशन से रजोकरी बार्डर तक ट्रैफिक भीड़ की संभावना होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से अप्सरा बॉर्डर और महाराजपुर बार्डर से गाजीपुर की ओर जाने वाले वाहनों के यातायात को डायवर्ट करने के कारण एनएच-24 पर भी भीड़भाड़ रहेगी।

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का महत्व: उद्योग विशेषज्ञ डॉ. अंकुर शरण के साथ बातचीत

आज की दुनिया में, जहां भारत तेजी से शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनता जा रहा है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। इस विषय पर हमने आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स के विशेषज्ञ डॉ. अंकुर शरण से बातचीत की, जो पिछले 16 वर्षों से इस उद्योग का हिस्सा रहे हैं और पूरे भारत में आपूर्ति श्रृंखला कार्य को संभाल चुके हैं।

प्रश्न: डॉ. शरण, आप हमें आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के महत्व के बारे में बताएं?

डॉ. अंकुर शरण: आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है जो किसी भी संगठन की सफलता और स्थिरता के लिए आवश्यक है। यह उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद करता है। एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला न केवल उत्पादन लागत को कम करती है बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी को भी सुनिश्चित करती है।

प्रश्न: भारत जैसे विकासशील देश में आपूर्ति श्रृंखला पेशेवर बनने का क्या महत्व है?

डॉ. अंकुर शरण: भारत तेजी से विकास की ओर अग्रसर है और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। ऐसे में, आपूर्ति श्रृंखला पेशेवरों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वे विभिन्न उद्योगों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और दक्षता बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और नवाचारों का उपयोग करके वे आपूर्ति श्रृंखला को और भी अधिक प्रभावी और लचीला बना सकते हैं।

प्रश्न: आपने अपने करियर में कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना किया है और उनसे कैसे निपटा है?

डॉ. अंकुर शरण: हर पेशे में चुनौतियाँ होती हैं, और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन भी इसका अपवाद नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में संचालन करना, विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के साथ तालमेल बिठाना, और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। लेकिन सही रणनीति, प्रौद्योगिकी का उपयोग और टीम वर्क के माध्यम से इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है।

प्रश्न: क्या संदेश देंगे आप युवा पेशेवरों को जो इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं?

डॉ. अंकुर शरण: आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि वे इस क्षेत्र में आने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य रखें। यह एक बहुत ही गतिशील और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन इसके साथ ही इसमें अपार संभावनाएँ भी हैं। नवीनतम प्रौद्योगिकियों के साथ खुद को अद्यतन रखें, और निरंतर सीखने की प्रक्रिया में लगे रहें।

भारतीय बाजार के लिए आपूर्ति श्रृंखला उद्योग का महत्व

कार्यक्षमता में सुधार:

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन व्यवसायों को अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और संचालन लागत को कम करने में मदद करता है। यह उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

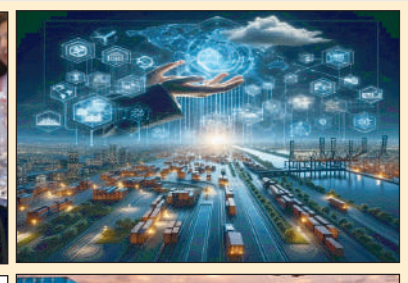

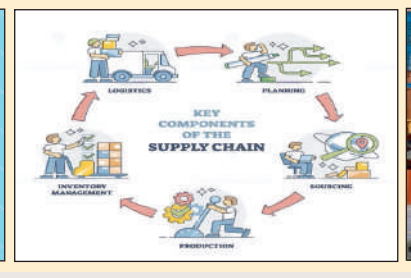

समय पर डिलीवरी:

एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला समय पर उत्पादों की डिलीवरी सुनिश्चित करती है। यह उपभोक्ताओं की संतुष्टि और ब्रांड की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है।

मांग की भविष्यवाणी:

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके बाजार की मांग की सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। इससे उत्पादन और वितरण की योजना बेहतर बनाई जा सकती है।

विपणन प्रतिस्पर्धा:

एक प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला भारतीय व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाती है। इससे भारतीय उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ती है।

जोखिम प्रबंधन:

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्राकृतिक आपदाओं, आर्थिक संकटों और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहता है। यह व्यवसायों को संकट के समय में स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है।

उत्पाद की गुणवत्ता:

एक अच्छी आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करती है कि उत्पाद उच्च गुणवत्ता के साथ उपभोक्ताओं तक पहुँचें। इससे ब्रांड की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।

स्थिरता:

आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह कंपनियों को उनकी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करता है, जैसे कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना और टिकाऊ सामग्री का उपयोग करना।

नवाचार:

आपूर्ति श्रृंखला में निरंतर सुधार और नवाचार व्यवसायों को बाजार में अद्वितीय बनाए रखते हैं। यह प्रतिस्पर्धियों से आगे बढ़ने में सहायक है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास:

आपूर्ति श्रृंखला उद्योग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करता है। यह क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

सरकारी नीतियों का समर्थन:

भारतीय सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी नीतियों को सफल बनाने में आपूर्ति श्रृंखला उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह देश के समग्र आर्थिक विकास में सहायक है।

भारतीय बाजार में आपूर्ति श्रृंखला उद्योग का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह न केवल व्यवसायों की सफलता के लिए आवश्यक है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

इस बातचीत के माध्यम से स्पष्ट होता है कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का वर्तमान समय में अत्यधिक महत्व है, और इसमें करियर बनाना एक समझदारीपूर्ण और लाभदायक निर्णय हो सकता है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ता जा रहा है, और इसमें कुशल पेशेवरों की आवश्यकता निरंतर बनी रहेगी।

Email - ankur.supplychain@gmail.com

क्या हैं क्राउडस्ट्राइक? आखिर ये कितना खतरनाक है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ

हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसमें यूजर्स के लैपटॉप पर एरर शो कर रहा है और कई यूजर्स का तो लैपटॉप खुद ही बंद हो गया है। आइए जानते हैं आखिर क्या है यह और कितना खतरनाक है।

बीते दिनों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके और अन्य सहित दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज उपयोगकर्ताओं को अपने लैपटॉप पर नीली स्क्रीन की समस्या दिखाई दे रही है। इससे उनके सिस्टम स्वचालित रूप से पुनरारंभ या बंद हो गए हैं। डेल टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों ने कहा है कि यह दुर्घटना हालिया क्राउडस्ट्राइक अपडेट के कारण हुई है।

क्राउडस्ट्राइक क्या है?

CrowdSrike एक साइबर सुरक्षा प्लेटफ़ॉर्म है जो उपयोगकर्ताओं और व्यवसायों को सुरक्षा समाधान प्रदान करता है। अंतिम बिंदुओं, कार्यभार और पहचान पर हमले के सहसंबंध के साथ एकल सेंसर और एकीकृत खतरा इंटरफ़ेस का उपयोग करके, फाल्कन आइडेंटिटी थ्रेट प्रोटेक्शन वास्तविक समय में पहचान-संचालित उल्लंघनों को रोकता है। यह बताया गया है कि बगी अपडेट क्राउडस्ट्राइक के फाल्कन सेंसर की खराबी और विंडोज सिस्टम के साथ टकराव के कारण हुआ है।

क्राउडस्ट्राइक ने त्रुटि स्वीकार की है और कहा है, ₹हमारे इंजीनियर इस समस्या को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और समर्थन टिकट खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है।₹ यह समस्या सुलझने के बाद कंपनी यूजर्स को अपडेट करेगी।

Microsoft ने पुष्टि की कि Azure आउटेज को शुक्रवार की शुरुआत में हल कर लिया गया था, लेकिन यह व्यवधान संभावित परिणामों की एक स्पष्ट याद दिलाता है जब महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा क्लाउड सेवाओं पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इस आउटेज ने एयरलाइंस, बैंक, सुपरमार्केट, मीडिया आउटलेट और अन्य व्यवसायों को प्रभावित किया है।

ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ क्या है?

ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ (बीएसओडी) एक गंभीर त्रुटि स्क्रीन है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिखाई देती है। ऐसा तब होता है जब सिस्टम किसी गंभीर समस्या के कारण क्रैश हो जाता है जो इसे सुरक्षित रूप से काम करने से रोकता है। जब यह त्रुटि होती है, तो कंप्यूटर अप्रत्याशित रूप से पुनरारंभ हो जाता है, और सहेजा न गया डेटा खो जाने की संभावना होती है।

इस मामले में, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ त्रुटि बताती है, "आपके पीसी में एक समस्या आ गई है और उसे दोबारा आरंभ करने की आवश्यकता है। हम बस कुछ त्रुटि जानकारी एकत्र कर रहे हैं, हम आपके लिए

Oppo का ये फोन जल्द होगा लॉन्च, दो खूबसूरत रंगों में मिलने वाले इस फोन के फीचर्स जानें

कंपनी भारत में Oppo K12x5G लॉन्च कर रही है। कंपनी ने अपकमिंग 5G फोन की लॉन्च डेट को लेकर भी जानकारी दे दी है। इतना ही नहीं, ओप्पो के इस पोन के डिस्प्ले, डिजाइन को लेकर भी जानकारियां सामने आ चुकी हैं।

ओप्पो अपने भारतीय ग्राहकों के लिए एक नया 5G फोन लॉन्च कर रहा है। कंपनी भारत में Oppo K12x5G लॉन्च कर रही है। कंपनी ने अपकमिंग 5G फोन की लॉन्च डेट को लेकर भी जानकारी दे दी है। इतना ही नहीं, ओप्पो के इस पोन के डिस्प्ले, डिजाइन को लेकर भी जानकारियां सामने आ चुकी हैं।

कब लॉन्च होगा Oppo K12x5G

Oppo K12x5G फोन को लेकर माना जा रहा है कि ये भारत में OnePlus Nord CE 4 के रिब्रांडेड वर्जन के रूप में लाया जा सकता है। अपकमिंग फोन को लेकर कंपनी कंफर्म कर चुकी है कि फोन इसी महीने लॉन्च किया जा रहा है। ओप्पो का ये फोन 29 जुलाई को लॉन्च किया जा रहा है।

Oppo K12x5G की खूबियां

Oppo K12x5G को डुअल रियर कैमरा यूनिट के साथ देखा जा रहा है। फोन वर्टिकल पिल-शेप्ड मॉड्यूल और सर्कुलर एलईडी फ्लैश यूनिट के साथ नजर आया है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन सेंटर होल पंच और टॉप पर फ्रंट कैमरा के साथ देखा जा रहा है। फोन के दायीं ओर एक वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन देखा जा रहा है।

वहीं Oppo K12x5G के लॉन्च के कंफर्म करते हुए कंपनी ने इस पोन को अपनी इंडिया वेबसाइट पर भी शोकेस किया है। फोन को लेकर जानकारी दी गई है कि डिवाइस भारतीय ग्राहकों के लिए ब्रीज ब्लू और मिडनाइट वाइलेट कलर में खरीद सकेंगे।

टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन को कॉर्नियल डैमेज का पता चला, जानें कॉन्टैक्ट लेंस लगाते समय क्या करें और क्या न करें?

दिल्ली में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद जैस्मीन भसीन ने कॉन्टैक्ट लेंस पहन रखा था जिसके बाद एक्ट्रेस की कॉर्नियल डैमेज हो गई। बता दें कि एक्ट्रेस, दिल्ली में अपने कार्यों के चलते आईं थी और एक्ट्रेस ने कॉन्टैक्ट लेंस पहना हुआ था फिर जैस्मिन को अचानक से दर्दनाक संवेदनाएं महसूस करने लगीं। हालांकि, वह अपनी कार्य प्रतिबद्धताओं को स्थगित नहीं करना चाहती थी और इसलिए, कार्यक्रम के लिए धूप का चश्मा पहना। हालांकि, कुछ देर बाद जैस्मिन को कुछ भी नजर नहीं आया और उन्हें अपनी टीम से मदद मांगनी पड़ी। बाद में रात में, जब वह जांच के लिए एक नेत्र विशेषज्ञ के पास गई, तो एक्ट्रेस को कॉर्नियल क्षति का पता चला और विशेषज्ञ ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। 34 वर्षीय एक्ट्रेस को ठीक होने में कम से कम चार से पांच दिन लगेंगे। फिलहाल, जैस्मिन अभी ठीक से देख नहीं पा रही है। रविवार दोपहर को, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक अपडेट साझा किया, "अब बेहतर है और ठीक हो रही हूं। आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद।"

कॉर्नियल क्षति एक डरावना मामला हो सकता है। जैस्मीन की स्थिति हमारा ध्यान इस ओर ले जाती है कि कॉन्टैक्ट लेंस पहनते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं।

अच्छी स्वच्छता बनाए रखें

जब भी आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनने या हटाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना हमेशा याद रखना चाहिए। याद रहे कि कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर नहीं सोना चाहिए।

कॉन्टैक्ट लेंस के घोल से धोएं

कॉन्टैक्ट लेंस को हटाने के बाद, आपको उन्हें कॉन्टैक्ट लेंस के घोल से धोना सुनिश्चित करना चाहिए। आप हमेशा कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन को रोजाना बदलना याद रखना चाहिए, भले ही आप कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग नहीं कर रहे हों।

मेकअप से पहले कॉन्टैक्ट लेंस पहनें

मेकअप लवर को सलाह दी जाती है कि मेकअप लगाने से पहले कॉन्टैक्ट लेंस पहनें और मेकअप हटाने के बाद ही कॉन्टैक्ट लेंस हटाएं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आंखों के अंदरूनी किनारे पर कभी भी ग्लिटर या आईलाइनर न लगाएं।

कॉन्टेक्ट लेंस को गर्म पानी से साफ करें

साप्ताहिक रूप से, हमें अपने कॉन्टैक्ट लेंस को गर्म पानी से धोना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें हर तीन महीने में एक नए जोड़े से बदला जाए।

ज्यादा न पहनें

लेंस उतना ही पहनना चाहिए जितना नेत्र विशेषज्ञ द्वारा सुझाया गया हो। आप अपने साथ चश्मे का एक जोड़ा भी रखना चाहिए, उस समय के लिए जब आप कॉन्टैक्ट लेंस हटाने की आवश्यकता होती है।

आंखों में जलन होने पर

आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंखों में जलन या लाली दिखाई देने पर कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस न पहनें। यदि कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद आंखों में लालिमा के साथ धुंधली दृष्टि आती है, तो आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।

सावन व्रत के दौरान ड्राई फ्रूट्स से बनाएं स्वादिष्ट और हेल्दी मिल्क शेक, नोट करें रेसिपी

सावन का महीना आज यानी 22 जुलाई से शुरु हो गया है। सावन के दौरान भगवान शिव को प्रसन्न करने और मानोकामना पूर्ण होने के लिए भक्तजन सावन के सोमावार को उपवास रखते हैं। व्रत रखने वाले लोगों के लिए ड्राई फ्रूट्स का शेक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है।

ड्राई फ्रूट्स का सेवन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता हैं। फाइबर से रिच सूखे मेवे का सेवन करने से बॉडी को ताकत और एनर्जी मिलती है। काजू, बादाम और अखरोट तीन सूखे मेवे से मिल्क शेक बनाकर पीने से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इस मिल्क शेक को पीने से घंटों तक भूख का एहसास नहीं होता है। अगर आप सावन के महीने में व्रत का पालन कर रही हैं तो फलाहार के तौर पर ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक पी सकते हैं। इसे पीने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है।

ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक के लिए सामग्री

-काजू - 1 टेबलस्पून -बादाम - 1 टेबलस्पून
-अखरोट - 2-3 गिरी -ठंडा दूध - 1 गिलास
-चीनी - स्वादानुसार

ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक बनाने का तरीका

व्रत के दौरान आप खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक एक बेहतरीन विकल्प है। सावन सोमवार के व्रत के दौरान भी ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक को पीना सबसे अच्छा विकल्प है। इसको बनाना काफी आसान है। सबसे पहले आप बादाम और अखरोट को रातभर के लिए पानी में भिगोकर रखें। फिर अगले दिन शेक बनाने के लिए बादाम छील लें। इसके बाद काजू, बादाम और अखरोट को मिक्सर जार में डालें और ग्राइंड कर लें। आपका बारीक पेस्ट तैयार है, फिर आप इसमें दूध और चीनी डालें। इसके बाद ढक्कन लगाकर दोबारा मिक्सर में चलाएं। एकदम यह थीक हो जाएगा इसके बाद इसे पी लें।

इन 5 जगहों को एक्सप्लोर किए बिना अधूरी है दिल्ली की ट्रिप, वीकेंड पर बनाएं प्लान

अगर आप भी दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप यहां की विविधता और धरोहर का आनंद ले सकते हैं। ऐसे में हम आपको दिल्ली के कुछ फेमस जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। जहां पर आपको एक बार जरूर जाना चाहिए।

दिल्ली में शॉपिंग करनी हो, या ऐतिहासिक स्थल देखना हो। यहां पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास जरूर मौजूद है। देश की राजधानी दिल्ली घूमने के लिहाज से एक बढ़िया जगह है। बता दें कि दिल्ली में शॉपिंग मॉल, स्ट्रीट फूड एरिया और कई ऐतिहासिक जगहें हैं। जहां पर आप घूम सकते हैं। हर साल भारी संख्या में पर्यकट दिल्ली को एक्सप्लोर करने के लिए यहां आते हैं। दिल्ली में आपको आधुनिकता और इतिहास का अनोखा संगम देखने को मिलता है।

ऐसे में अगर आप भी दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप यहां की विविधता और धरोहर का आनंद ले सकते हैं। ऐसे में इस आर्टिकल के जरिए हम आपको दिल्ली के कुछ फेमस जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आपको एक बार जरूर जाना चाहिए।

लाल किला

दिल्ली घूमने के दौरान लाल किला को एक्सप्लोर करना न भूलें। लाल किला को रेड फोर्ट भी कहा जाता है और यह एक ऐतिहासिक जगह है। साल 1648 में मुगल शासक शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। यह दिल्ली की सबसे फेमस जगहों में से एक है। यहां पर भारत के ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी आते हैं। मंगलवार से लेकर रविवार तक लाल किला पर्यटकों के लिए खुला रहता है।

अक्षरधाम

अक्षरधाम मंदिर को स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे भारत में फेमस है।

जामा मस्जिद

दिल्ली के जामा मस्जिद को मस्जिद-ए-जहांनुमा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रमुख और ऐतिहासिक मस्जिद होने के साथ भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। साल 1656 में मुगल शासक शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस मस्जिद में करीब 25,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं।

कनॉट प्लेस

दिल्ली में घूमने के लिहाज से कनॉट प्लेस एक बेहतरीन जगह है। यह जगह दिल्ली का अट्रैक्शन प्वाइंट है। इस जगह को सीपी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कनॉट प्लेस को दिल्ली का दिल भी कहा जाता है। कनॉट प्लेस में शॉपिंग से लेकर घूमने तक के लिए काफी कुछ है। यहां पर कई फेमस रेस्टोरेंट भी हैं। कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क काफी ज्यादा फेमस है।

इंडिया गेट

दिल्ली का इंडिया गेट यहां का मेन अट्रैक्शन है। ऐसे में आपको दिल्ली में एक बार इंडिया गेट जरूर जाना चाहिए। इंडिया गेट 42 मीटर ऊंचा एक युद्ध स्मारक है, जिसको प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए इंडियन सोल्जर की याद में बनाया गया था। इसके मुख्य आकर्षण का केंद्र अमर जवान ज्योति और इसके आसपास के पार्क हैं।

सेलेक्ट सिटी वॉक

दिल्ली के साकेत में स्थित सलेक्ट सिटी वॉक मॉल एक फेमस शॉपिंग मॉल है। यह जगह एंटरटेनमेंट, फूड और सोशल एक्टिविटी के लिए बेस्ट प्लेस है। इस मॉल में कई कैफे, रेस्तरां और फूड कोर्ट हैं।

सावन के महीने में हाथों पर लगाएं भगवान शिव और झूला मेहंदी डिजाइन, सौभाग्य की प्राप्ति होगी

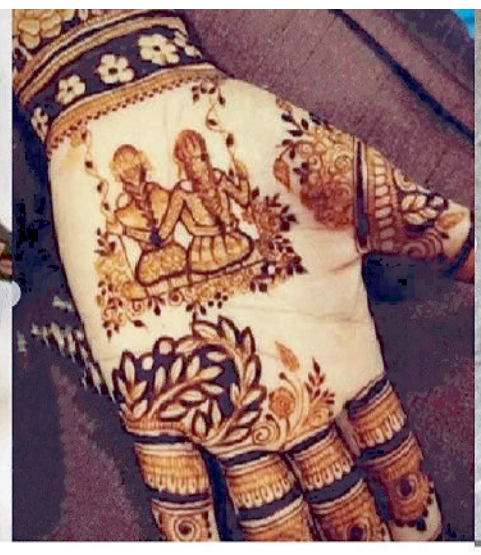

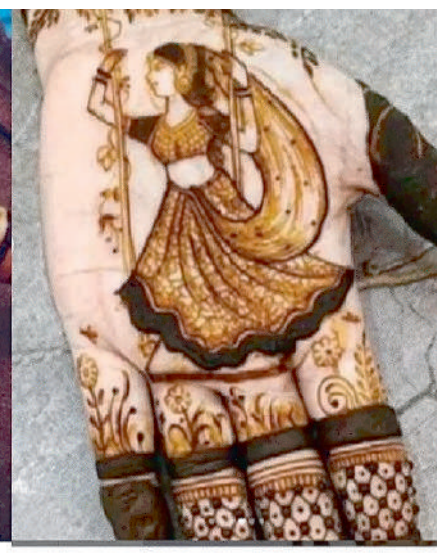

सावन का महीना शुरु हो चुका है। इस महीने में महिलाओं को श्रृंगार करना और हाथों पर मेहंदी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। आप भी अपने हाथों पर झूला मेहंदी डिजाइन को लगा सकती हैं। यह मेंहदी आप भी लगा सकते हैं।

सावन का महीना हिंदू धर्म बेहद ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा होती है। सावन के महीने में श्रृंगार का काफी महत्व होता है। सावन महीने में महिलाओं को श्रृंगार करना और हाथों पर मेहंदी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं, इस माह में सावन के झूलों का विशेष महत्व होता है। सावन माह में मेहंदी लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सावन के महीने में कई सारे त्योहार आते हैं, जहां हाथों में मेहंदी लगाने का मौका मिल जाता है। सावन में तीज का त्योहार और रक्षाबंधन का पर्व आता है। तब सभी महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। अगर आप भी मेहंदी लगवाने की डिजाइन सोच रहे हैं तो हम आपको इस लेख में बताते हैं।

भगवान शिव और झूला मेहंदी डिजाइन

सावन के दौरान आप इस मेहंदी के डिजाइन को अपने हाथों में सजवाना चाहते हैं, तो आप इस डिजाइन को जरुर ट्राई करें। एक हथेली पर भगवान शिव और माता पार्वती के डिजाइन को बनाया गया है। इसके साथ उंगली पर ऊं नमः शिवाय लिखवा सकते है। दूसरे हाथ में आप झूले पर बैठी महिला का डिजाइन बनवा सकते हैं। आसपास फूल के डिजाइन तैयार कर सकते है।

दोनों हाथ में बनाएं झूला वाला मेहंदी डिजाइन

सावन के माह में आप भी अपने दोनों हाथों में झूला मेहंदी डिजाइन बना सकते हैं। इसके के लिए आपको दोनों हाथों में झूले के डिजाइन बनाने होंगे। आसपास खाली जगह पर फूल और पत्तियों के डिजाइन बना सकते हैं।

पेपर लीक 2500 करोड की इंडस्ट्रीज, बेवफा NTA

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। NEET विवाद पर सुप्रीमकोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाओ पर चीफ जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड की बेंच के सामने सोमवार को भी चौथी सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओ के वकील ने री एग्जाम की मांग की। एडवोकेट ने इस पर 2015 के तन्वी सरवाल के फैसले का हवाला दिया। जब 44 स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल किया था।इसके बाद ऑल इंडिया प्री मेडिकल 2015 एग्जाम कैंसिल कर दिया था।

सुनवाई के दौरान NTA एनटीए ने माना कि 3300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गलत पेपर दिया गया था। इन्हें SBI की जगह केनरा बैंक का पेपर बाटा गया।

सीजेआई ने कहा कि आरोपियो के बयान अलग अलग है।पेपर लीक 4 मई की रात को हुआ। जाहिर है कि लीक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नहीं, बल्कि स्ट्रांग रूम वाल्ट से पहले हुआ था। सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा के साथ संजय हेगड़े मैथ्यूज नेदुम्परा याचिकाकर्ताओ की ओर से जबकि सालिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता NTA और केंद्र की ओर से पक्ष रख रहे थे। वकील नेंदूम्परा ने तो यहां तक कह डाला कि पेपर लीक मामला 2500 करोड की

इंडस्ट्रीज बन गया है। यह गिरोह बद्ध हो रहा है।पेपर हर साल लीक होता है। इसकी वजह में उन्होने बताया कि 50,000 सरकारी मेडिकल सीटें है।कैपिटेशन फीस लाख से 1 करोड रूपये के बीच है।कई सालों से पेपर लीक हो रहा है। 2013, 2014, 20161 उन्होने कहा कि हरियाणा के जिन सेंटर की बात की बात हो रही थी, वे तब भी इसमें शामिल थे। वकील नेदुम्परा ने बताया कि लातूर, राजकोट, एजूकेशन हब नहीं है।NTA ने गलत डेटा दिखाया है। दूसरी ओर हेगड़े ने कहा कि CBI की जांच सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं है।इसमें कई राज्य शामिल है।एजेंसी इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि लीक स्थानीय था। हेगड़े ने कहा कि NEET सिर्फ एक क्वालीफिकेशन है।यदि आप NEET क्वालीफाई है, तो आप केवल सरकारी सीटो के लिए ही योग्य नहीं है। बल्कि कई विदेशी मेडिकल कॉलेजिज में भी NEET स्कोर के जरिये एडमिशन मिलता है। 164 कट ऑफ पर लगभग 13 लाख कैंडिडेट्स ने NEET क्वालीफाई किया है।हुडा ने कहा कि अगर कोर्ट दोबारा नीट पर विचार नहीं कर रहा है तो कम से कम नीट क्वालीफाईड लोगो को दोबारा परीक्षा देने के लिए कहा जाना चाहिए, जो करीब 13 लाख लोग है। हुडा ने कहा कि पूरी तरह से सिस्टम फेल हुआ है। एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी नहीं की। NTA की खामियों को गिनाते हुए कहा कि एनटीए ने रिजल्ट जारी कर दिए है।उन्होने ऑल इंडिया रैंक नहीं दी।उन्होने परीक्षा केंद्रो का क्रम नहीं दिया है।परीक्षा केंद्रों की आऑल इंडिया रैंक सीरियलों, रोक दिए है।सुप्रीमकोर्ट में सरकार ने 3 तीन गलती मानी है। इनमें 8 सेंटरों के 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गलत पेपर दिया गया था। इन्हें एसबीआई की जगह केनरा बैंक का पेपर बांटा गया था। ऐसा झज्जर के तीन सेंटरों में हुआ। झज्जर के हरदयालस्कूल में कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। जबकि यहां पेपर सही दिया गया था। यह एक घोर गलती थी। अगली तारीख 26 जुलाई।

पर्यावरण में होने वाले तापमान परिवर्तन को केवल पौधों रोपण से ही बचाया जा सकता है

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। आज से पवित्र श्रावण मास का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर ऑल इंडिया मीडिया क्लब (रजि) की दिल्ली एनसीआर प्रेसिडेंट वरिष्ठ पत्रकार सुषमा रानी ने अपनी टीम के साथ मयूर विहार इलाके में पौधारोपण किया।

इस अवसर पर पत्रकार सुषमा रानी ने कहा कि ऑल इंडिया मीडिया क्लब के चेयरमैन डॉ एमक्यू मलिक और राष्ट्रीय महासचिव पत्रकार मनोज टंडन के आह्वान पर दिल्ली एनसीआर में पौधारोपण किया जा रहा है।

सुषमा रानी ने कहा कि आज के दौर में जिस तरह से पर्यावरण तमाम तरह की चीज़ों से प्रभावित हो रहा है उसके लिए न केवल वृक्ष लगाने जरुरी है बल्कि उनका ध्यान रखना भी जरूरी है। पर्यावरण सुरक्षा और मनुष्य के जीवन में सीधा संबंध है। लेकिन आजकल मनुष्य वन नष्ट कर के और कृषि योग्य भूमि को अपने अंधे लालच में बेच कर अट्टालिकाएं खड़ी करने में ये भूल गया कि इसका प्रकारती के संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

#एक_पेड़_एक_जीवन #पेड़_लगाए_जीवन_पाए

#पेड़_न_होंगे वन न होंगे #वन न होंगे वर्षा न होगी #वर्षा न होगी नदियां न होंगी #नदियां न होंगी जल न होगा #जल न होगा #कल_जीवन_न_होगा

जैसा बोएंगे वैसा ही कल सामने आयेगा

#कानून_प्रकृति_का_है_कायदा

#Concrete_के_जंगल_बंद_करो

यही समय है सही समय है पर्यावरण में होने वाले तापमान परिवर्तन को केवल पेड़ लगाकर ही यथास्थिति बरकरार रखी जा सकती है। लगातार आग लगने के कारण नष्ट होते वन और प्राकृतिक संपदा को बचाए।

दिल्ली सरकार की तरफ से कांवरियो के स्वागत के लिए जोर-शोर से कावड़ शिविर लगाने की तैयारी चल रही

सुषमा रानी

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार दिल्ली में कांवड़ियों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। कांवड़ियों को बेहतर सुविधाएँ मिल सके इसलिए सरकार शहर भर में ज़ोर-शोर से चल रही कांवर शिविर लगाने की तैयारियाँ कर रही है। इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए साझा करते हुए राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि, दिल्ली सरकार दिल्ली भर में 185 कांवर शिविरों के ज़रिए कांवड़ियों के लिए सबसे बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित कर रही है। इस दिशा में हमारे शिविर हाई क्वालिटी वाटर प्रूफ टेंट, मेडिकल फै सि लि टी ज़, सा फ़ - पा नी, शौचालय, फ़र्नीचर सहित तमाम सुविधाओं से लैस होंगे।

उन्होंने कहा कि, सावन के पवित्र महीने में शिवभक्तों की सेवा में कोई कमी नहीं छूटेगी। कांवड़ियों के लिए बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए हर जरुरी कदम उठाए जाएँगे। बता दें कि, दिल्ली में कांवड़ियों का आगमन 25 जुलाई के बाद से होगा और अगले 2-3 दिन में सभी कांवड़ शिविर पूरी तरह तैयार होंगे। पूर्वी दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली व शहादरा जिलें दिल्ली में कांवड़ियों के एंट्री-एग्जिट पॉइंट होते है। ऐसे में इन तीनों जिलों में कांवड़ियों की सुविधा के लिए सबसे अधिक शिविर लगाए जा रहे है।

उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील करते हुए कहा कि, सरकार तो अपनी तैयारियाँ कर रही लेकिन दिल्ली के लोग भी धर्म के इस कार्य में भाग ले, अपना सहयोग दे और जहां भी ज़रूरत हो वहाँ कांवड़ियों की मदद करें।

उनने कहा कि, आज से सावन के महीने की शुरुआत हो गई है। इस दौरान देशभर में ख़ासतौर पर उत्तर भारत में कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर आते है। दिल्ली में इन कांवड़ियों के स्वागत के लिए केजरीवाल सरकार शहर भर में कांवर शिविर लगाती है और उसमें कांवड़ियों के लिए सबसे शानदार सुविधाएँ सुनिश्चित की जाती है।

उन्होंने कहा कि, दिल्ली में केजरीवाल सरकार इस साल 185 कांवर शिविर लगवा रही है। इनमें पूर्वी दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली व शहादरा जिलें जो दिल्ली में कांवड़ियों के एंट्री-

एग्जिट पॉइंट होता है। ऐसे में यहाँ सबसे ज्यादा शिविर लगाए जा रहे है ताकि बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने बाद भी भीड़ का आसानी से प्रबंधन हो सकें। सबसे ज़्यादा 38 शिविर शाहदरा ज़िले में लगाए जा रहे है। उत्तरी पूर्वी, सेंट्रल और पूर्वी दिल्ली में क्रमशः 29,22 व 19 शिविर लगाए जा रहे है।

उन्होंने कहा कि, केजरीवाल सरकार प्रतिबद्ध है कि वो अपने शिविरों में कांवड़ियों को सबसे शानदार सुविधाएँ दे सके। ऐसे में जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, तब से कांवड़ियों के लिए हाई-क्वालिटी वाटरप्रूफ टेंट, मेडिकल फैसिलिट्ज, साफ़-पानी, शौचालय, फर्नीचर आदि सुविधाओं का इंतज़ाम किया जाता है। ताकि लंबी कांवड़ यात्रा कर आ रहे कांवड़ियों को उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो।

उन्होंने कहा कि, इस साल भी दिल्ली का राजस्व विभाग अपने कांवड़ शिविरों में ये सभी सुविधाएँ सुनिश्चित कर रहा है। जून से ही कांवड़ शिविरों को लेकर राजस्व विभाग की तैयारियाँ जारी है और लगातार मिनिस्टर इंचार्ज और राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण किया गया है।

उन्होंने कहा कि, दिल्ली में कांवड़ शिविर लगाने को लेकर सभी तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी है। दिल्ली में 25 जुलाई के बाद से कांवड़ियों का आगमन शुरू हो जाएगा। ऐसे में आने वाले 2-3 दिन में कांवड़ शिविर से जुड़ी सभी तैयारियाँ पूरी हो जाएगी।

सरकारी कर्मचारी भी वैलिड, संघ से हटाया प्रतिबंध

परिवहन विशेष। एसडी सेठी। देश के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। इस आदेश में केंद्र सरकारों के द्वारा 1966 1970, और 1980 के उन आदेशो में संशोधन किया गया है, जिसमें कुछ अन्य संस्थाओ के साथ-साथ। आरएसएस की शाखाओ और अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर कडे दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे।

इस आदेश का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वागत किया है।दरअसल आरोप है कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों की संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी।आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कडी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था। इसी के मद्देनजर ही कर्मचारी अपनी पेंशन लाभ से वंचित होने के डर से संघ की गतिविधियों में शामिल होने से बचते थे। बता दे कि इस बीच मध्यप्रदेश, सहित कई राज्य सरकारो ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था। इस मामले में एक वाद इंदौर की अदालत में चल रहा था।जिस पर अदालत ने केंद्र

सरकार से सफाई मांगी थी।इसी पर कारवाई करते हुए 8 जुलाई को एक आर्डर जारी करते हुए उक्त प्रतिबंधों को खत्म करने की घोषणा कर दी। दरअसल केंद्र सरकार ने यह आदेश ऐसे समय पर किया है, जब कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा में कुछ तनातनी और खटास की खबरे आती रही है। संघ पर आरोप है कि भाजपा के असहयोगी रवैये के कारण संघ ने लोकसभा चुनाव में पर्याप्त सहयोग नहीं किया। जिसके कारण भाजपा को बहुमत से दूर रह जाना पडा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ दिन पूर्व ही ऐसी टिप्पणी की थी, जिसे केंद्र सरकार की कडी आलोचना के बतौर देखा गया। ये ही नहीं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता इंद्रेश कुमार ने भी जनता के द्वारा अहंकारी लोगो को सबक सिखाने की नसीहत तक दे डाली थी। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने तो यह तक कह डाला था कि अब हमें संघ की कोई जरूरत ही नहीं है। तब भी यह टिप्पणी केंद्र सरकार के खिलाफ मानी गई थी। हालांकि बाद में इंद्रेश ने भी यू ट्रेन लेकर बयान से पल्ला झाड लिया था। इस वक्त मजबूत विपक्ष सत्ता पक्ष को हर मसले पर घेरने की फिराक में है। संसद में भी इस मसले पर हंगामा होने की कवायद की जा रही है। उधर आरएसएस ने भी प्रतिबंध को गलत माना है। संघ के वरिष्ठ अधिकारी राजीव तुली के मुताबिक केंद्र सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य कहा है।उन्होने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के निर्माण मे लगा हुआ संगठन है।वह पूरे देश में हर एक जगह पर हर वर्ग के लिए काम करता है।किसी प्रकार के भेदभाव के बिना राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करने की आजादी रहती है। उन्होने कहा कि जो सरकारी सेवाओ मे रहते हुए संघ के साथ जुडकर राष्ट्र निर्माण की अपनी इच्छा पूरी करना चाहते थे, अब ऐसे लोगों के लिए संघ के दरवाजे खुल गए हैं।

ज्ञापन समझौता दिव्यांग जनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है

सुषमा रानी

नई दिल्ली, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पूरे देश में दिव्यांगता से संबंधित सभी मामलों को देखता है

समावेशी समाज बनाने के विभाग के सतत प्रयासों के तहत आज 22 जुलाई को विभाग के अधीनस्थ विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों ने विभिन्न प्राइवेट संस्थानों व स्टार्टअप्स के साथ एक साथ 72 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली स्थित डॉ अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार व राज्य मंत्री बी.एल वर्मा जी की गरिमामयी उपस्थिति में इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। आज यहां हुए समझौता ज्ञापनों से समाज में बहुत व्यापक व सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कार्य होगा। आज यहां पर सरकारी और गैर- सरकारी संगठनों के साथ 72 समझौता ज्ञापन हुए हैं। इससे पहले कभी इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं किया गया। आज का यह कार्यक्रम एक सराहनीय उपलब्धि है। पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के तहत आज हमारे देश की बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो दिव्यांगों के जीवन को सुगम बनाने वाले कई

उपयोगी उपकरणों का देश के अंदर कम दामों में निर्माण कर रही हैं। डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उन्हें रोजगार देने के लिए शासकीय प्रयासों के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिव्यांगजन हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, उन्हें हमारे सद प्रयासों की जरुरत है। इस प्रयास में सरकार के साथ- साथ विभिन्न संगठनों का प्रभावी तौर पर कार्यकरना बेहद जरूरी है।

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि हमारा यह प्रयास होना चाहिए की देश के निर्माण में, दिव्यांगजनों की भूमिका को सशक्त बनाया जाए। यहां मौजूद सभी संगठनों द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में किए गए कार्य भी बेहद सराहनीय हैं। हमारी सरकार और विभाग ऐसे संगठनों के साथ कार्य करने के लिए हमेशा से इच्छुक रही है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और एक समावेशी माहौल बनाने की दिशा में कार्य करते हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल.वर्मा ने कहा- आज यहां हुए समझौता ज्ञापन दिव्यांगजनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। दिव्यांग लोगों में अपार क्षमताएं होती हैं, उन्हें बस अवसर की आवश्यकता होती है। दिव्यांगजनों में व्याप्त कार्य करने की अदम्य इच्छाशक्ति आम जनमानस के लिए भी प्रेरणास्त्रोत का कार्य करती है। आज विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा विभिन्न संगठनों से किए गए समझौता ज्ञापन उन्हें यह मंच देने का कार्य करेंगे।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि आज दिव्यांगजनों के प्रति समाज के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रह है। आज इस कार्यक्रम में कई ऐसे प्राइवेट संस्थान आएं हैं जिन्होंने व्यापक स्तर पर दिव्यांगों को रोजगार देने का कार्य किया है, जो एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में बेहतरीन पहल है। उन्होंने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में जहां बेहतरीन पॉलिसी बनाने का कार्य कर रही है, वहीं सरकार प्राइवेट संगठनों के साथ मिलकर चीजों के स्केलअप करने में भी मदद कर रही है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित इस समझौता ज्ञापन कार्यक्रम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, प्रौद्योगिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिव्यांगजनोंके परिवारों को सशक्त बनाने, दिव्यांगजनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों के सृजन, क्लब फुट की रोकथाम और इलाज के साथ-साथ प्रशिक्षकों/शिक्षकों की क्षमता निर्माण जैसी नवीनतम तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। इस कार्यक्रम में देशभर की विभिन्न कंपनियों और स्टार्टअप्स जिसमें Zomato, IIT Madras, EnABle India, Neo Motion, Cure India, Assam Rifiles, Radio Udaan आदि शामिल रहे। कार्यक्रम में विभाग के संयुक्त सचिव राजीव शर्मा, राजेश यादव, उप महानिदेशक किशोर बाबूराव सुरवाड़े सहित वरिष्ठ अधिकारीगण, राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक और कंपनियों के प्रतिभागीगण मौजूद रहे।

यूनियनों का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना होता है, लेकिन कई बार आरोप लगते हैं कि यूनियन नेता अपने निजी स्वार्थों के लिए मजदूरों का इस्तेमाल करते हैं

092666 55590:

गुमराह करने के तरीके:

1. *राजनीतिक एजेंडा:* कुछ यूनियन नेता अपने राजनीतिक हित साधने के लिए मजदूरों का समर्थन हासिल करते हैं।

2. *भ्रष्टाचार:* आर्थिक लाभ के लिए नेता मजदूरों के फंड का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।

3. *गलत जानकारी:* मजदूरों को आधी-अधूरी या गलत जानकारी देकर अपने पक्ष में फैसले करवाते हैं।

नुकसान:

1. *वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकना:* मजदूरों के वास्तविक मुद्दे सुलझने की बजाय, वे नेताओं के निजी एजेंडों में उलझ जाते हैं।

2. *भरोसे की कमी:* मजदूरों का यूनियन और उसके नेताओं पर भरोसा कम हो जाता है।

3. *अधिकारों का हनन:* मजदूरों के अधिकार और हित उपेक्षित रह जाते हैं।

उपाय:

1. *पारदर्शिता:* यूनियन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए।

2. *स्वतंत्र निगरानी:* यूनियन के कामकाज की स्वतंत्र निगरानी हो।

3. *शिक्षा और जागरूकता:* मजदूरों को उनके अधिकारों और यूनियन के कामकाज के बारे में शिक्षित किया जाए।

यूनियन की संरचना और उद्देश्य सही हों तो यह मजदूरों के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग होता है, तो यह मजदूरों के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है।

यह एक आम समस्या है जहां चालाक लोग अपने प्रभाव और संपर्कों का इस्तेमाल करके बेहतर ड्यूटी हासिल कर लेते हैं, जबकि ईमानदार मजदूरों को कम आकर्षक या कठिन कार्य दिए जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं:

1. *पारदर्शी ड्यूटी असाइनमेंट:*

- ड्यूटी असाइनमेंट की प्रक्रिया को पारदर्शी और स्पष्ट बनाया जाए।

- एक सिस्टम बनाया जाए जहां ड्यूटी का आवंटन योग्यता, अनुभव, और निष्पक्षता के आधार पर हो।

2. *निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र:*

- एक स्वतंत्र निगरानी समिति गठित की जाए जो ड्यूटी असाइनमेंट की समीक्षा कर सके।

- एक शिकायत निवारण तंत्र हो जहां मजदूर अपनी समस्याओं को बिना डर के रिपोर्ट कर सकें।

3. *रोटेशन पॉलिसी:*

- ड्यूटी में रोटेशन की नीति अपनाई जाए ताकि सभी मजदूरों को समान अवसर मिलें।

- एक निश्चित अवधि के बाद ड्यूटी बदलने की व्यवस्था हो।

4. *प्रशिक्षण और विकास:*

- सभी मजदूरों को आवश्यक प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे विभिन्न प्रकार की ड्यूटी संभाल सकें।

- उनके कौशल और योग्यता को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए।

5. *संवाद और सहभागिता:*

- मजदूरों के साथ नियमित संवाद और बैठकें आयोजित की जाएं ताकि उनकी समस्याएं और सुझाव सुने जा सकें।

- निर्णय प्रक्रिया में मजदूरों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

6. *अकादमिक और प्रोफेशनल समर्थन:*

- मजदूरों के लिए प्रोफेशनल समर्थन और सलाहकार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे अपने करियर को बेहतर बना सकें।

इन उपायों से न केवल ईमानदार मजदूरों को उचित ड्यूटी मिल सकेगी बल्कि उनके काम का सम्मान भी बढ़ेगा।

आज है तो कल है वृक्ष है तो जल है

सुषमा रानी

नई दिल्ली। 22 जुलाई को योगेंद्र कुमार हेड वार्डर तिहाड़ जेल के नेतृत्व में पी एम श्री केंद्रीय विद्यालय टैगोर गार्डन में वन मोहत्सव के शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में फलदार एवम अक्सीजन देने वाले वृक्ष का पौधारोपण किया तथा बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया इस अवसर पर योगेंद्र कुमार ने विद्यार्थियों से निवेदन किया की जिस विधार्थी ने पौधारोपण किया है वो ही उसकी देखभाल करेगा तथा प्रधानाचार्य संजय कुमार ने भी विद्यार्थियों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया, इस अवसर पर बी के पांडेय, इंदर सोनी, अनिल चौधरी, वीरेंद्र कुमार, जोगेन्दर कुमार, देविंदर मखीजा, हरीश भारद्वाज, सुनील बाल्मीकि, गौरव, राम निवास यादव, ने भी विद्यार्थियों को जागरूक किया।

जहां बरसे पत्थर, वहां बरसे फूल... हिंसा के एक साल बाद निकली जलाभिषेक यात्रा, पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

साधु-संतों की अगुवाई में हरियाणा ब्रज क्षेत्र और राजस्थान के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में पहुंचे। शांतिपूर्ण यात्रा के लिए ढाई हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए और ड्रोन से भी नजर रखी गई। पिछले साल हिंसा को देखते हुए पुलिस प्रशासन चौकन्ना रहा। कई जगहों पर नाकेबंदी कर गाड़ियां की तलाशी ली गई।

गुरुग्राम/नूंह। सावन के पहले सोमवार पर साढ़े तीन सौ साधु-संतों की अगुवाई में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच निकाली गई। ढाई हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में यात्रा शांतिपूर्ण यात्रा संपन्न हो गई।

रास्ते भर यात्रा की ड्रोन से निगरानी और वीडियोग्राफी कराई गई। यात्रा में जाने वाले वाहनों समेत सभी गाड़ियों की गहनता से तलाशी ली गई। पिछले साल नूंह के नल्हड़ महादेव मंदिर में पथराव के बाद हिंसा को देखते हुए इस बार पुलिस प्रशासन पहले से ही चौकन्ना था। इसको लेकर कई दिनों से तैयारियां की जा रही थीं। यात्रा में हरियाणा, ब्रज क्षेत्र और राजस्थान के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

गुरुग्राम से निकाला गई यात्रा

गुरुग्राम से निकाली गई यात्रा में सोमवार सुबह आठ बजे सेक्टर-10ए श्री कृष्ण मंदिर में शहर के श्रद्धालु जमा हुए। यहां से राजीव नगर गुफा वाला मंदिर की साध्वी आत्मचेतन गिरि, सराय आश्रम के स्वामी मुक्तानंद महाराज, बाबड़ा बाकीपुर के स्वामी अमरदास महाराज, कादीपुर के स्वामी सेवादास महाराज, सराय आश्रम के स्वामी फतेनाथ महाराज और भीमगढ़ खेड़ी मंदिर की साध्वी आदिशक्ति के नेतृत्व जलाभिषेक यात्रा नूंह के लिए रवाना हुई।

आसपासके जिलों से पहुंचे श्रद्धालु

गुरुग्राम के पटौदी समेत हरियाणा के फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, पलवल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ब्रज क्षेत्र और राजस्थान के इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा से पहुंचे। भोंडसी, सोहना, नूंह के कंवरसिका, रेवासन समेत कई जगहों पर यात्रा का स्वागत किया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत किया।

भोलेनाथ के जयकारों और भजनों के साथ झूमते-गाते हजारों श्रद्धालु सुबह साढ़े 11 बजे नूंह के नल्हड़ महादेव मंदिर पहुंचे। यहां गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। मंदिर में जलाभिषेक के बाद यात्रा फिरोजपुर झिरका के झीर्ण मंदिर और फिर शाम साढ़े चार बजे पुन्हाना के राधा कृष्ण श्रृंगार मंदिर पहुंची।

यात्रा के साथ-साथ चले पुलिसकर्मी

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गुरुग्राम से यात्रा की शुरुआत होते ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी साथ-साथ चले। जगह-जगह पुलिसकर्मियों की तैनात थी। रास्ते में ड्रोन से भी निगरानी की गई। भोंडसी, सोहना के रायपुर, रेवासन, नूंह में नाके लगाकर यात्रा में शामिल वाहनों समेत नूंह की तरफ जाने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी ली गई।

अफवाह न फैले, इसके लिए रविवार शाम छह बजे से ही 24 घंटे के लिए नूंह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं। इसके अलावा निगरानी के लिए जगह-जगह सीसीटी कैमरे भी लगाए गए थे। सोहना, नूंह के कई जगहों पर वज्र वाहन, वरुण वाहन, दंगा नियंत्रण वाहन, आरएएफ की टीम भी सुरक्षा व्यवस्था में लाठी और हेलमेट के साथ तैनात रही।

अरावली पहाड़ी पर कमाडों की रही तैनाती

पिछले साल 31 जुलाई 2023 को नूंह में हिंदू संगठनों द्वारा निकाली गई ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में नल्हड़ महादेव मंदिर के पास पथराव हो गया था। इसके बाद नूंह, गुरुग्राम समेत अन्य जगहों पर हिंसा फैल गई थी। इसमें छह लोग मारे गए थे और 80 से ज्यादा घायल हो गए थे। पिछले साल हुई हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने शांतिपूर्ण यात्रा के लिए पहले से ही कमर कस ली थी।

नल्हड़ महादेव मंदिर व तिजारा रोड पर स्थित पांडवकालीन शिवमंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अरावली की वादियों की तलहटी में बने हैं। गत वर्ष उपद्रवी नल्हेश्वर मंदिर के पीछे की पहाड़ियों में छिप गए थे। इस बार इन अरावलियों पहाड़ियों की जांच व सुरक्षा के लिए ड्रोन से कड़ी नजर रखी गई।

पहाड़ी के पास कमाडों की भी तैनाती रही। जिस भी मंदिर में यात्रा पहुंची, यहां पहले ही डाग स्क्वायड तैनात थे। वहीं, नूंह में भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई थी। वाहनों के न चलने और 90 प्रतिशत दुकानें बंद होने से नूंह में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात दिखे। बताया गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वतः दुकानों को बंद किया था।

ऑन डिमांड लग्जरी कार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, छह सदस्य हुए गिरफ्तार; होटल के बाहर से चंद मिनटों में उड़ा देते थे वाहन

नोएडा पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने ऑन डिमांड कार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों के पास से चोरी की 10 लग्जरी कार बरामद की गई हैं। जानिए आखिर ये कैसे होटल के सामने से चंद मिनटों में कार चोरी कर लेते थे?

नोएडा। नोएडा दिल्ली एनसीआर से ऑन डिमांड लग्जरी कार चोरी करने वाले गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।

कोतवाली पुलिस ने सोमवार को नोएडा सेक्टर-113 एफएनजी रोड पर भारत अस्पताल के पास से इन आरोपितों को अरेस्ट किया है। गिरोह के सदस्य पंजाब, नार्थ ईस्ट समेत 11 राज्यों में चोरी की कारों को शौकीन लोगों को खपा रहे थे।

बताया गया कि ये बदमाश होटल आदि के बाहर खड़ी मंहगी कार को चंद मिनटों में उड़ा ले जाते हैं। पुलिस ने आरोपितों के पास से चोरी की 10 कार बरामद की हैं।

16 मिनट में नोएडा की गेटेड सोसायटी से तीन तोला सोना ले उड़े चोर

सेक्टर 20 कोतवाली के सेक्टर 25 स्थित जलवायु विहार में रहने वाली मीडियाकर्मी ऋचा बाजपेयी के बंद फ्लैट में चोरों ने 16 मिनट में चोरी को अंजाम दिया। दो चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं।

पड़ोस में रहने वाली आंटी ने पीड़िता को चोरी की घटना की जानकारी दी। चोर फ्लैट से तीन तोले वजन के सोने के गहने चोरी कर ले गए। पीड़िता ने कोतवाली में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। मीडियाकर्मी ने अधूरी शिकायत दर्ज करने का आरोप लगाया है।

पड़ोस की आंटी ने कॉल कर बताई घटना

ऋचा बाजपेयी ने बताया कि जलवायु विहार के वाई-70 फ्लैट में किराये पर रहती हैं। पिछले दिनों किसी काम से कानपुर अपने घर गई हुई थीं। 18 जुलाई की सुबह पड़ोस में रहने वाली आंटी का फोन आया और उन्होंने फ्लैट का ताला टूटा होने व चोरी के बारे में बताया।

शाम को नोएडा वापस आने पर पाया कि फ्लैट का ताला तोड़कर चोरी की गई है। फ्लैट में सारा सामान तो सुरक्षित था, लेकिन अलमारी खुली हुई थी। सोने की दो चैन, दो जोड़ी सोने के ईयरिंग व एक पेंडेंट था। तीनों का वजन करीब तीन तोले है।

गत्ता फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान, टीम ने छह घंटे में पाया काबू

गत्ता फैक्टरी में आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। बताया गया कि शॉर्ट-सर्किट के चलते रविवार रात को फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। वहीं दमकल की टीम ने करीब सात घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पढ़िए आखिर फैक्ट्री में आग लगने से क्या-क्या बड़ा सुनसान हुआ है?

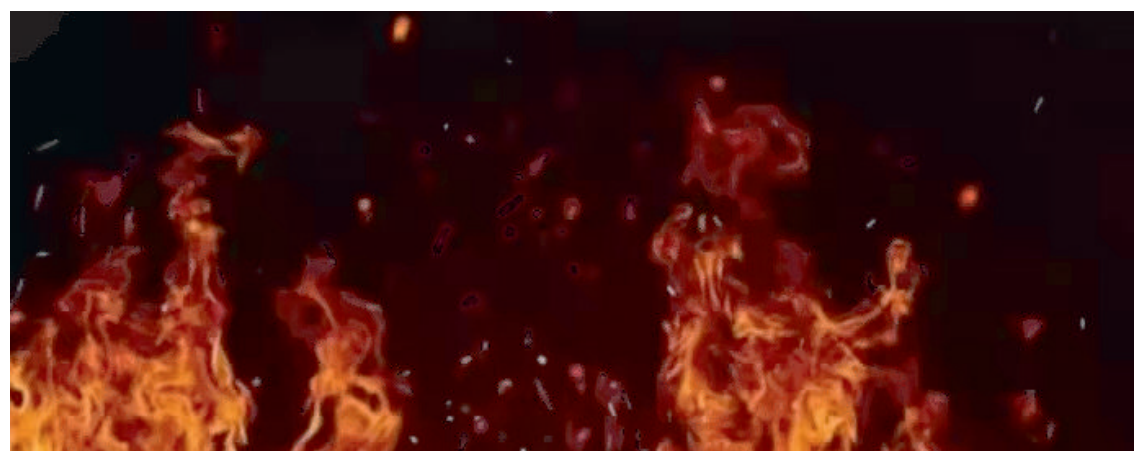

गुरुग्राम। शॉर्ट-सर्किट होने के चलते गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर दो दमकल वाहनों ने मौके पर जाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। गत्ते में आग फैलने के कारण आग पर काबू पाने में अधिक समय लगा।

वहीं, सोमवार सुबह करीब छह बजे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग के कारण हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

मोदी केसिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है फैक्ट्री

दिल्ली मेरठ मार्ग पर मोदी केसिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फैक्ट्री है। फैक्ट्री में गत्ता आधारित उत्पाद बनाए जाते हैं। बीती रात करीब दो बजे फैक्ट्री में अचानक आग लग गई।

बताया गया कि गत्ता होने के कारण आग कुछ ही देर में फैल गई और दूसरे उपकरणों को अपनी चपेट में ले लिया। सुरक्षाकर्मियों ने शुरू में आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। कुछ देर बाद उन्होंने दमकल विभाग को सूचित कर दिया।

टीम ने कड़ी मशक्कत से पाया आग पर काबू

सूचना मिलने पर दो दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू का प्रयास किया। गत्ते के रोल में आग फैलने कारण आग पर काबू पाने में समस्या का सामना करना पड़ा। सुबह सात बजे तक दमकलकर्मी आग बुझाने का प्रयास करते रहे। करीब छह घंटे की मशक्कत बाद आग पर काबू पाया जा सका।

बताया गया कि आग के कारण कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। मोदी समूह के पीआरओ डीडी कौशिक का कहना है कि आग में गत्ते समेत दूसरे उपकरण भी जलकर राख हो गए हैं। आग के हुए नुकसान के विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

एफएसओ अमित कुमार के अनुसार, प्राथमिक अवलोकन में आग कारण शार्ट सर्किट हो सकता है।

होटल में सीनियर टैक्स एनालिस्ट की मौत, भाई को देर रात किया था जीवन का आखिरी मैसेज

गाजियाबाद। कौशांबी थाना क्षेत्र के होटल लैमन ट्री के एक कमरे में सोमवार सुबह दिल्ली के रहने वाले एक सीनियर टैक्स एनालिस्ट का शव मिला। देर रात को युवक ने अपने भाई को संदेश भी भेजा था। फोन नहीं उठाने पर स्वजन मौके पर पहुंचे तो घटना का पता चला।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में डिप्रेशन की अत्याधिक दवाई खाकर जान देने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

शख्स के बेसुध होने की मिली सूचना

सोमवार सुबह करीब 10 बजे कौशांबी थानाध्यक्ष को होटल लेमन ट्री के प्रबंधक ने कॉल कर कमरा नंबर 610 में एक युवक के बेसुध हालत में होने की सूचना मिली। युवक के स्वजन उसे पास के निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।

गुरुग्राम की कंपनी में था कार्यरत

मृतक की पहचान प्रीतमपुरा दिल्ली के इमिल बिव जोसेफ के रूप में हुई। वह गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में बतौर सीनियर टैक्स एनालिस्ट के पद पर कार्यरत थे। पुलिस होटल में पहुंची तो कमरे की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। मौक पर साकेत दिल्ली के एक निजी अस्पताल का डॉक्टर का पर्चा मिला। इसमें डिप्रेशन की दवाइयां लिखी हुई थी। पर्चा दिसंबर 2023 का था।

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और मीडिया के उलझे रिश्ते

प्रो. (डॉ.) संजय द्विवेदी,

"माननीय प्रधानमंत्री जी हम आभारी हैं कि आप हमारे बीच आए। मेरी ऑन दी जॉब लर्निंग अब शुरू हो गई है और 2024 तक मैं देश की सबसे अच्छी जर्नलिस्ट होने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूं कि तब आपसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने का मौका मुझे मिलेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।" ये शब्द हैं भारत की पहली एआई बॉट एंकर सना के। आर्टिफिशनल इंटेलिजेंस के मीडिया जगत में बढ़ते इस्तेमाल की कई संभावनाएं हैं। इसी में से एक है कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री एक एआई एंकर से देश के भविष्य और योजनाओं के बारे में चर्चा करते दिखें।

दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 'टेक्स्ट टू स्पीच' फीचर की बदौलत अब भारतीय न्यूजरूम में मशीन को इंसानी चेहरे में ढालकर खबरें पेश की जा रही हैं। पिछले साल अप्रैल के महीने में इंडिया टुडे ग्रुप ने एआई एंकर से समाचार बुलेटिन का प्रसारण शुरू किया था। लॉन्च कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एंकर का परिचय देते हुए कहा गया था कि वह ब्राइट है, सुंदर है, उम्र का उन पर कोई असर नहीं होता है और न ही कोई थकान होती है, वो बहुत सारी भाषाओं में बात कर सकती हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को फिर से परिभाषित करने, मानवीय क्षमता की सीमाओं को पार करने और अभूतपूर्व पैमाने पर उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार देने के लिए तैयार है। मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में, एआई का आगमन कंटेंट क्रिएटर्स को सामग्री निर्माण के लिए शक्तिशाली उपकरणों से सशक्त बना रहा है, नए अनुभवों को अनलॉक कर रहा है और कलात्मक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों का उपभोग करने, बनाने और उनसे जुड़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रहा है।

हाल के कुछ समय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और पत्रकारिता का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह रहा है। मौजूदा समय में भारत की मेनस्ट्रीम मीडिया का बड़ा हिस्सा विज्ञापन पर निर्भर होकर काम कर रहा है। ऐसे में तकनीक के जरिये डेटा के आधार पर समाचार बुलेटिन प्रस्तुत करना और अन्य काम भी इंसान की जगह मशीन की बदौलत होने ने मीडिया इंडस्ट्री के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्रकारिता के भविष्य से लेकर पत्रकारिता करने वालों के भविष्य को लेकर भी संकट खड़ा होने की बात कही जा रही है। लेकिन एआई पत्रकारिता वास्तव में क्या है? क्या यह चिंता का एक विषय है या फिर सूचना जगत में एक ऐसी नई क्रांति है, जो पत्रकारिता के सही आयाम स्थापित करने में कामयाब हो पाएगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पत्रकारिता

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन के लगभग सभी पहलूओं समेत पत्रकारिता में भी शामिल हो गई है। डिजिटल मीडिया की वजह से जाने-अनजाने में ही एआई तकनीक पर आधारित कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वह यू-ट्यूब के एल्गोदिरम की वजह से आपको दिखते वीडियो हों या वेबसाइट पर दिखने वाले विज्ञापन। सभी का एक कारण एआई तकनीक ही है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव की वजह से एआई पत्रकारिता में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मीडिया कंपनियां अपने कंटेंट को अधिक बूस्ट करने के लिए एआई की मदद ले रही हैं। लेख लिखने से लेकर बुलेटिन प्रसारित करने तक में एआई का सहारा लिया जा रहा है। दुनिया भर के बड़े-बड़े मीडिया हाउस एआई द्वारा लिखे लेख को प्रकाशित कर रहे हैं। एक तरफ तो यह काम को आसान और तेजी से कर रहा है, दूसरी ओर यह कई सवाल भी खड़े करता है जिसमें विश्वसनीयता और अखंडता सबसे पहले है। साथ ही क्या सजृनशीलता पर आधारित क्षेत्र में एआई से डेटा आधारित बातचीत और जानकारी, पत्रकारिता के धरातल पर काम कर पाएगी? पत्रकारिता के सबसे मजबूत और शुरुआती मूल्य 'ग्राउंड रिपोर्टिंग' का भविष्य इससे बच पाएगा?

खतरे में पत्रकारों की नौकरियां

इंसान की जगह मशीन के इस्तेमाल होने का पहला खतरा इंसानों पर ही पड़ता है। 'न्यूज़जीपीटी', दुनिया का पहला समाचार चैनल है, जिसका पूरा कंटेंट आर्टिफिशल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया जा रहा है। चैनल के प्रमुख एलन लैवी ने इसे खबरों की दुनिया का गेम चेंजर कहा था, क्योंकि ना इसमें कोई रिपोर्टर है और ना ही यह किसी से प्रभावित है। यहां यही बात मीडिया जगत में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ा खतरा है। जैसे-जैसे मीडिया के क्षेत्र में एआई का प्रभुत्व बढ़ रहा है, वहां मौजूदा लोगों की नौकरियों पर तकनीक का कब्जा होने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। लेखन, संपादन, एंकरिंग, प्रस्तुतीकरण तक के सारे कामों में एआई का सहारा लिया जा रहा है।

बीबीसी द्वारा प्रकाशित एक समाचार के अनुसार साल 2020 में माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ी संख्या मे 'एमएसएन' वेबसाइट के लिए लेखों के चयन, क्यूरेटिंग, हेडलाइन तय करने और एडिटिंग करने वाले पत्रकारों की जगह स्वचलित सिस्टम को अपनाने की योजना बनाई। खबर के अनुसार कंपनी ने एआई तकनीक के सहारे खबरों के प्रोडक्शन के कामों को पूरा करना तय किया। माइक्रोसॉफ्ट जैसी अन्य टेक कंपनियां मीडिया संस्थानों को उनका कंटेंट इस्तेमाल करने के लिए भुगतान करती हैं। इन सब कामों के लिए पेशेवर पत्रकारों की मदद ली जाती आई है, जो कहानियां तय करने, उनका प्रकाशन कैसे होना है, हेडलाइन तय करने जैसे काम करते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के एआई तकनीक के इस्तेमाल के बाद से लगभग 50 न्यूज प्रोड्यूसर्स को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी।

ठीक इसी तरह साल 2022 के अंत में अमेरिकी टेक्नोलॉजी न्यूज वेबसाइट 'सीएनईटी' एआई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चीजें अलग ही स्तर पर ले गई। कंपनी ने एआई प्रोग्राम के तहत लिखे गए दर्जनों फीचर लेख चुपचाप तरीके से प्रकाशित किए। जनवरी 2023 तक कंपनी ने इन सब अटकलों की पुष्टि नहीं की थी, जिसे केवल एक प्रयोग बताया जा रहा था। इतना ही नहीं एसोसिएटेड प्रेस ने भी अपनी कहानियों के लिए एआई का इस्तेमाल किया। ये सब बातें बताती हैं कि कैसे समाचारों को चुनने, उनको व्यवस्थित करने के लिए काम करने वाले मीडिया के पेशेवरों की नौकरियां एआई ले रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन अभी से न्यूजरूम के भीतर उसकी मौजूदगी से मीडिया पेशवरों की नौकरियों पर संकट बनना शुरू हो चुका है। डायच वेले के अनुसार हाल ही में यूरोप के सबसे बड़े पब्लिकेशन हाउस 'एक्सल स्प्रिंगर' ने कई संपादकीय नौकरियों को एआई में बदल दिया है। स्प्रिंगर में नौकरियों की कटौती से मीडिया उद्योग के रोबोट पर निर्भरता की आशंकाओं में तेजी ला दी है।

न्यूजरूम में एआई एंकर

भारत समेत कई अन्य देशों में न्यूज एंकर के तौर पर कम्प्यूटर जनित मॉडल यानी एआई एंकर समाचार पढ़ते नज़र आ रहे हैं। बहुत हद तक इंसानी तौर पर दिखने वाले ये न्यूज एंकर कॉर्पोरेट मीडिया हाउस के मुनाफे वाले दृष्टिकोण से हितैषी हैं, क्योंकि इन्हें न कोई सैलरी की आवश्यकता है, ना छुट्टी की। ये 24 घंटे और सातों दिन डेटा के आधार पर काम कर सकते हैं। भारत की पहली एआई न्यूज एंकर सना के लॉन्च के समय इसी तरह के शब्द कहे गए थे कि वह बिना थके लंबे समय तक काम कर सकती है।

द गार्डियन के अनुसार साल 2018 में चीन की न्यूज एजेंसी 'शिन्हुआ' पहला एआई न्यूज एंकर दुनिया के सामने लाई। इस एजेंसी के किउ हाओ पहले एआई एंकर हैं, जिसने डिजिटल वर्जन पर समाचार प्रस्तुत किया। शिन्हुआ और चीनी सर्च इंजन सोगो द्वारा यह एआई एंकर विकसित किया गया है। प्रकाशकों ने चीन के वार्षिक वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस के क्रार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की थी। इसी से जुड़ी दूसरी के अनुसार पिछले वर्ष चीन ने एआई महिला न्यूज़ एंकर रेन जियाओरॉन्ग को लॉन्च किया। चीन सरकार केंद्रित पीपल्स डेली अखबार ने दावा किया है कि इस एआई न्यूज एंकर ने हजारों न्यूज एंकर्स से स्किल सीखे हैं और वह 365 दिन 24 घंटे लगातार खबरें बता सकती है। चीन के अलावा कुवैत भी अपना एआई न्यूज एंकर लॉन्च कर चुका है। हाल ही में 'न्यूज 18' के पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रीय चैनल की तरफ से भी एआई एंकर के बारे में बात की गई। इस एंकर का नाम एआई कौर है। हाल ही में रूस के स्वोए टीवी ने स्नेज़ना तुमानोवा को पहले वर्चुअल मौसम की खबर प्रस्तुत करने वाले के रूप में पेश किया।

इस तरह से दुनिया के अलग-अलग मीडिया संस्थानों की ओर से एआई तकनीक के न्यूज एंकर को लॉन्च किया जा रहा है। एक के बाद एक एआई न्यूज एंकर के लॉन्च को मीडिया की नई क्रांति और बदलाव बताया जा रहा है। अब यह देखना होगा कि सूचना के क्षेत्र में एआई समावेशिता, विश्वसनीयता स्थापित कर पाती है या नहीं। क्योंकि अगर अब तक लॉन्च एआई एंकर्स के रूप-आकार को लेकर बात करे तो उससे पूरी तरह समावेशिता गायब है। लॉन्च एंकर का आकार यूरो सैंट्रिक ब्यूटी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर गढ़ा गया है जैसे गोरा रंग, एक ख़ास तय किस्म की बॉडी आदि। सूचना के क्षेत्र में प्रस्तुतिकरण में इस तरह से पूर्वाग्रहों को और स्थापित करने का काम किया जा रहा है।

एआई की दुनिया और विश्वसनीयता

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन यह देखना वास्तव में बहुत दिलचस्प होगा कि यह पत्रकारिता को किस तरह से बदलेगा। क्योंकि आज क्लिकबेट पत्रकारिता, फेक न्यूज और प्राइम टाइम में चिल्लाने वाली पत्रकारिता का दौर है। ऐसे में क्या रोबोट, इंसानी रवैये के इतर विवेक के साथ पत्रकारिता करेंगे? प्रसिद्ध मीडिया स्तंभकार पामेल फिलिपोज ने कहा है कि एआई और उसके इस्तेमाल से पैदा खतरे वास्तविक हैं। एआई अधिक बहुस्तरीय समस्या को पैदा कर सकता है, जैसे एआई दुष्प्रचार अधिक फैला सकता है।

फिलिपोज ने आगे कहा है कि फेक न्यूज अब व्हाट्सएप टेक्स्ट और तस्वीरों के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं और एआई की पूरी क्षमता रॉ डेटा को पुर्नजीवित करना है। इस तरह बहुत से पत्रकार और मीडिया पेशवरों का मानना है कि एल्गोदिरम और ऑटोमेशन पर बढ़ती निर्भरता से पत्रकारिता की विश्वसनीयता कम होने का खतरा है।

एआई न्यूज एंकर या पत्रकारिता में एआई की निर्भरता सूचना क्षेत्र के भविष्य के लिए दोधारी तलवार है। एक तरफ इससे मीडिया के नयेपन और संचार के क्षेत्र की अपार संभावनों पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं इसे नैतिक और जिम्मेदारी तय करने के लिए रेग्यूलेशन और निरीक्षण की आवश्यकता भी है। ऐसे दौर में जहां मीडिया में पहले से ही ग्राउंड रिपोर्ट, खोजी पत्रकारिता और जनपक्ष की कमी है, उस समय में एआई तकनीक का बढ़ता प्रभाव सूचनाओं से मानवीय पक्ष को खत्म करने वाला ज्यादा नजर आ रहा है।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

स्कूटर बाजार के 50 प्रतिशत हिस्से पर ई-स्कूटर का कब्जा है, लेकिन सुविधाएं नहीं - राजीव चुग, ट्रम्प ईवी पार्ट्स

परिवहन विशेष न्यूज

पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटर का बाजार ग्रोथ कर रहा है। जहां करीब 50 फीसदी कब्जा महसूस किया जा रहा है। वहीं सुविधाएं देने में कंपनियां फिसड्डी साबित हो रही है। कंपनियां केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचकर अपना मुनाफा कमाने में लगी हुई है। भारत में बड़े, मझोले और छोटे शहरों में सैकड़ों कंपनियों के छोटे-बड़े शोरूम खुल गए हैं।

ऑटोमोबाइल में एक्सपर्ट रखने वाले राजीव चुग का कहना हैं कि भारत में लगभग हज़ारों-लाखों की संख्या से अधिक इलेक्ट्रिक स्कूटर सड़क पर दौड़ रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सवारी ऑटो और लोडिंग ऑटो भी दौड़ रहे हैं। इसमें ई-स्कूटर की संख्या अधिक है। इन वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं। इसके साथ ही सर्विस सेंटर की भी कमी बनी हुई है। चार्जिंग स्टेशन नहीं होने से लोग इन वाहनों 50 किमी से अधिक ले जाने में डर रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज किसी की 60 किमी हैं तो किसी की 100 हैं। ऐसे में जिन लोगों ने यह वाहन खरीदे हैं वे इसे बाहर ले जाने में डर रहे हैं। यह इसलिए नहीं डर रहें हैं कि कहीं भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। कहीं भी किसी के घर में चार्ज भी करते है तो इसमें छह घंटे लगते हैं। ऐसे में लोग इन वाहनों का पुरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए फास्ट चार्जिग स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता हैं ताकि लोग इन वाहनों का पुरा उपयोग कर सके।

उन्होंने कहा कि भारत में जितने ई-स्कूटर निर्माता हैं एक-दो को छोड़कर उनके पास स्पेयर पार्ट्स हैं ही नहीं और ज्यादातर ई-स्कूटर वाहनों में सेफ्टी किट भी नहीं होती है। न ही किसी कंपनी द्वारा अपने स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। अगर किसी का ई-स्कूटर खराब होता हैं तो वह किसी भी मैकेनिक से ठीक करवा सकें। वाहनों के लिए सर्विस सेंटर और मैकेनिक भी होने चाहिए। इससे की इलेक्ट्रीक वाहन में किसी तरह की समस्या आती है तो इसे दूर किया जा सके। इसलिए कुछ लोगों का ई-स्कूटर खरीदने का मन तो होता हैं परंतु इन सब कारणों से उनका मोह भंग हो रहा हैं।

कभी पहाड़ों की रानी की शान थी पेडल रिक्शा की सवारी अब बन जाएगी अतीत की कहानी

परिवहन विशेष न्यूज

मसूरी शुरू से ही देशी-विदेशी लोगों की पसंदीदा जगह रही है। ब्रिटिश काल में भी मसूरी आकर माल रोड पर पैडल रिक्शा का लुत्फ़ उठाना शान की बात मानी जाती थी। अंग्रेज़ और तत्कालीन राजा-रजवाड़े हाथ रिक्शा पर बैठकर माल रोड घूमने आते थे। लेकिन समय के साथ मसूरी में हाथ और पैडल रिक्शा की जगह ई-रिक्शा चलाने की मांग तेज़ी से उठने लगी है।

मसूरी में पैडल रिक्शा संचालन का पुराना इतिहास है। माना जाता है कि शहर में हाथ रिक्शा का इस्तेमाल 1850 से हो रहा है। दरअसल, मसूरी में घोड़ागाड़ी हर जगह नहीं जा सकती थी, इसलिए अंग्रेज हाथ रिक्शा से माल रोड या दूसरी जगहों पर जाते थे। जिन्हें चार लोग खींचते थे। मजदूर संघ के तत्कालीन सचिव देवी गोदियाल ने बताया कि हाथ रिक्शा चलाना बहुत मुश्किल काम था।

1995 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के तत्कालीन उपनिदेशक हर्षमंदर ने कर्मचारी संघ की मदद से हाथ रिक्शा का संचालन बंद करवा दिया था। उस समय हाथ रिक्शा के संचालन में करीब 428 लोग जुड़े हुए थे। अकादमी की मदद से सरकार ने प्रत्येक रिक्शा चालक को साइकिल या पैडल रिक्शा खरीदने के लिए 8,000 रुपये दिए। तभी से साइकिल रिक्शा का संचालन शुरू हुआ और आज भी जारी है। समय के साथ पैडल रिक्शा संचालक अब ई-रिक्शा की मांग करने लगे हैं। इसके लिए वे स्थानीय प्रशासन से अनुमति और सरकार से आर्थिक मदद चाहते हैं।

इतिहासकार जयप्रकाश उत्तराखंडी बताते हैं कि 1862-63 में चार्लीबिल्ली की मालकिन लेडी डिक मसूरी में पहला रिक्शा लेकर आई थीं। 1875 के बाद हैप्पी वैली के अंग्रेज उद्योगपति मर्चेंट ने चार्लीबिल्ली में रिक्शा बनाने की फैक्ट्री लगाई। 1901 में मर्चेंट ने रबर से बना शानदार सिंगल रिक्शा बनाया और मसूरी में सिंगल और डबल रिक्शा चलने लगे।

अंग्रेजों के अलावा मसूरी में रहने वाले राजा, रजवाड़े, नवाब, जागीरदारों के पास अपने पैडल रिक्शा और वेतनभोगी कर्मचारी थे। आजादी के बाद अंग्रेज चले गए। रजवाड़े, नवाब और जागीरदारों का दबदबा भी कम होता गया। यहां का व्यापारिक ढांचा चरमरा गया और फैक्ट्रियों में रिक्शा बनाने वाले मजदूरों का काम लगभग बंद हो गया। 1950 के बाद मशहूर लेखक राहुल सांकृत्यायन ने मसूरी के मजदूरों की दुर्दशा का मुद्दा उठाने के लिए 'मजदूर संघ' बनाया। 1960 में जब मसूरी में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी तो मसूरी के पैडल रिक्शा मजदूरों को रोजगार मिलना शुरू हुआ।

मसूरी मजदूर संघ के सचिव और पैडल रिक्शा संचालक संजय टम्टा के मुताबिक माल रोड पर 121 साइकिल रिक्शा संचालित हो रहे हैं। सभी रिक्शा संचालक अब ई-रिक्शा चलाना चाहते हैं। स्कूटर और बाइक के जमाने में साइकिल रिक्शा का चलन नहीं रहा। माल रोड पर आने वाले ज्यादातर पर्यटक साइकिल रिक्शा पसंद नहीं करते। 40 साल से रिक्शा चला रहे 65 वर्षीय सम्पति लाल का कहना है कि सरकार को ई-रिक्शा संचालन में सहयोग करना चाहिए।

मसूरी नगर पालिका के ईओ राजेश नैथानी का कहना है कि इससे पहले पैडल रिक्शा संचालकों की मांग पर ई-रिक्शा और गोल्फ कार्ट का ट्रायल कराया गया था। ट्रायल में ई-रिक्शा का संचालन सफल नहीं रहा। गोल्फ कार्ट का संचालन ठीक रहा। रिक्शा संचालकों से वार्ता के बाद शहर में गोल्फ कार्ट संचालन की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

जीएसटी कम हुआ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आएगी तेजी, बजट से इंडस्ट्री को ये हैं उम्मीदें

परिवहन विशेष न्यूज

देश में 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों की आम बजट से कुछ मांगें हैं। कंपनियों की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर जीएसटी दर कम करने से लेकर फेम-3 सब्सिडी लागू करने तक कई मांगें की गई हैं।

ईवी निर्माताओं ने केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं। ईवी निर्माताओं ने कहा है कि सरकार ईवी पर कम जीएसटी लगाती है, लेकिन ईवी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर 18-28 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है। निर्माताओं की मांग है कि कच्चे माल पर लगाए जाने वाले जीएसटी को संशोधित किया जाए। इसके अलावा निर्माताओं को उम्मीद है कि सरकार फेम-3 सब्सिडी को लेकर कोई घोषणा करेगी।

फेम-3 सब्सिडी से ईवी निर्माताओं को काफी सहारा मिलेगा। इसके अलावा कुछ ईवी निर्माता निर्यात पर भी ध्यान दे रहे हैं, ताकि मेक इन इंडिया उत्पाद विदेशों में अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए सरकार को कुछ नई नीतियों की घोषणा करनी चाहिए, ताकि वैश्विक विस्तार में मदद मिल सके। निर्माताओं ने अपनी मांगें रखते हुए कहा कि अगर 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है तो कुछ ऐसी नीति लाना जरूरी है जो भारत की प्रतिभा को आगे ले जाए। इसके अलावा सरकार को बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लेकर भी कुछ घोषणा करनी चाहिए। ईवी निर्माताओं ने यह भी कहा कि सरकार को स्वदेशी ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर भी ध्यान देना चाहिए।

हीरो मोटोकॉर्प इस साल किफायती इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन करेगी लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

भारत की शीर्ष दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प इस वित्त वर्ष में किफायती इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) लॉन्च करने की योजना बना रही है। कंपनी के सीईओ निरंजन गुप्ता ने 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में यह खबर साझा करते हुए कहा कि कंपनी का लक्ष्य इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार का नेतृत्व करना है।

निरंजन गुप्ता ने बताया कि हीरो मोटोकॉर्प के पास अपने इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय को तेज़ी से बढ़ाने के लिए एक विस्तृत योजना है। कंपनी अपने मौजूदा विदा वी1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर के अलावा एक मज़बूत EV उत्पाद लाइनअप बनाएगी। इस वित्तीय वर्ष में मध्यम और किफ़ायती सेगमेंट में नए मॉडल लॉन्च किए जाएँगे।

विदा इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत वर्तमान में 1-1.5 लाख रुपये के बीच है, जिसमें राज्य सब्सिडी भी शामिल है। कार्यकारी अध्यक्ष पवन मुंजाल ने बताया कि हीरो मोटोकॉर्प ने एथर एनर्जी के साथ मिलकर दोपहिया ईवी के लिए भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क बनाया है। इसके अलावा, ज़ीरो मोटरसाइकिल के साथ उनकी साझेदारी विभिन्न ग्राहक वर्गों के लिए नई ईवी मोटरसाइकिल विकसित करने में मदद करेगी।

पवन मुंजाल भारत में विदा वी1 स्कूटर की सफलता से खुश हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसके लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने पहले ही अपने विदा ईवी स्कूटर को 100 से ज़्यादा शहरों में लॉन्च कर दिया है।

निरंजन गुप्ता ने जयपुर और जर्मनी में अपने आरएंडडी केंद्रों में कंपनी के अभिनव कार्यों पर भी प्रकाश डाला, जिसका लक्ष्य सभी क्षेत्रों में एक मजबूत उत्पाद लाइनअप बनाना है। हीरो मोटोकॉर्प की योजना अधिक प्रीमियम उत्पाद पेश करने और अपने अंतरराष्ट्रीय, एक्सेसरीज और मर्चेंडाइज कारोबार का विस्तार करने की है।

कंपनी अपने वैश्विक कारोबार को बढ़ाने और शीर्ष दस बाजारों को लक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वे अपने एक्सेसरीज और मर्चेंडाइज कारोबार का विस्तार करने के अवसर भी तलाश रहे हैं। पिछले साल हीरो मोटोकॉर्प ने कई प्रीमियम उत्पाद लॉन्च किए और आने वाले सालों में भी इस प्रवृत्ति को जारी रखने की योजना है।

विशाल ग्राहक आधार, व्यापक वितरण नेटवर्क और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला क्षमता के साथ, हीरो मोटोकॉर्प सफलता के लिए अपने पैमाने का लाभ उठाता है। निरंजन गुप्ता ने बदलते वैश्विक और उपभोक्ता रुझानों से आगे रहने के लिए उत्पाद विकास और निर्णय लेने में गति के महत्व पर जोर दिया।

महिला ई-रिक्शा चालकों को शोषण से बचाएं

परिवहन विशेष न्यूज

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ की मध्य क्षेत्र प्रभारी गीता सोनी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर महिला ई-रिक्शा चालकों को शोषण से बचाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया है।

ज्ञापन में गीता सोनी ने कहा है कि रेलवे स्टेशन पर महिला ई-रिक्शा चालकों से अवैध वसूली की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को लाने-ले जाने और अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाली महिला ई-रिक्शा चालकों का उनके ठेकेदारों द्वारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है। ये सभी महिलाएं भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध छत्तीसगढ़ प्रदेश वाहन चालक संघ की सदस्य हैं।

गीता सोनी ने कहा कि ये महिला चालक सुबह से रात तक ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करती हैं। ठेकेदारों द्वारा महिला ई-रिक्शा चालकों से 1500 से 2000 रुपए अवैध वसूली की जा रही है।

उन्होंने कहा कि पैसे न देने पर 200 रुपए का चालान काटा जा रहा है, जिससे इन महिला चालकों को अपने परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है। गीता सोनी ने बताया कि इससे पहले कलेक्टर और डीआरएम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुई है।

ज्ञापन में उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास चार्जिंग प्वाइंट और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग की है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ई-रिक्शा महिला चालकों की समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है।

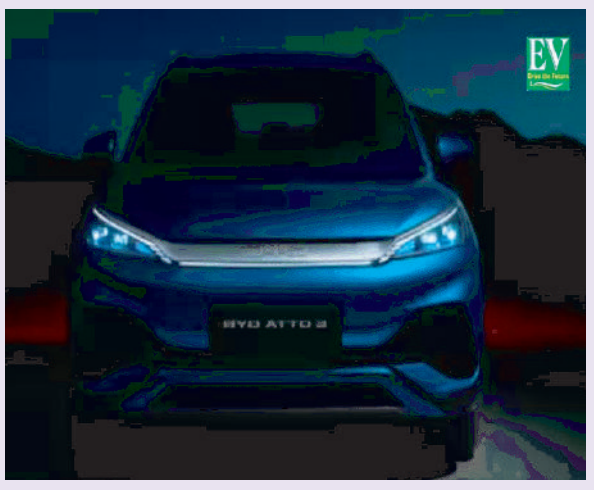

आ रही बीवाईडी की सस्ती इलेक्ट्रिक कार

परिवहन विशेष न्यूज

चीनी कार निर्माता कंपनी बीवाईडी ने हाल ही में अपनी लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार बीवाईड Atto-3 के दो नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं। माना जा रहा है कि ये वेरिएंट टाटा और महिंद्रा की कारों को सीधी टक्कर दे पाएंगे। इसके अलावा ये नया वेरिएंट MG ZS EV को भी सीधी टक्कर दे पाएगा।

बीवाईड Atto-3 बाजार में उपलब्ध टाटा, महिंद्रा और एमजी कारों से लंबी है लेकिन इस कार की ऊंचाई इन कारों से काफी कम है। इस कार का ग्राउंड क्लीयरेंस सिर्फ 175 mm है। साथ ही इसका व्हीलबेस 2720 mm है। कंपनी ने Atto-3 इलेक्ट्रिक कार में 18 इंच के बड़े व्हील दिए हैं। साथ ही कार में 440 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है।

पावरट्रेन की बात करें तो बीवाईडी Atto-3 इलेक्ट्रिक कार में दो बैटरी पैक दिए गए हैं। इसमें 49.92 kWh और 60.48 kWh बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है। 49.92 kWh बैटरी पैक की मदद से यह इलेक्ट्रिक कार सिंगल चार्ज में 468 किलोमीटर की रेंज प्रदान करती है। बड़े बैटरी पैक की मदद से यह कार 521 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है। यह इंजन 204 bhp की अधिकतम पावर भी जनरेट करने में सक्षम है।

दूसरी ओर एमजी जेडएस ईवी में 50.3 kWh बैटरी पैक है जो कार को 461 किमी की रेंज देता है। टाटा नेक्सन ईवी में 40.5 kWh बैटरी पैक है जो इसे 465 किमी की रेंज देता है।

बीवाईडी Atto-3 की एक्स-शोरूम कीमत 25 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 34 लाख रुपये तक जाती है। एमजी जेड एस ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 19 लाख रुपये से शुरू होकर 25.44 लाख रुपये तक जाती है। इसके अलावा टाटा नेक्सन ईवी लॉन्ग रेंज की एक्स-शोरूम कीमत 17 लाख रुपये से शुरू होकर 19.49 लाख रुपये तक जाती है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने सब्सिडी के लिए परिवहन विभाग को जारी किए 30 करोड़ रुपए

परिवहन विशेष न्यूज

छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में 25 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकार ने पिछले एक साल से अटकी सब्सिडी को जारी करने के लिए 30 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें से पहले चरण में 10 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए खरीदारों के खातों में 15 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।

प्राथमिकता के आधार पर पहले वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी की राशि मिलेगी। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य वाहनों को भुगतान किया जाएगा। राज्य में नई सरकार के सत्ता में आते ही परिवहन विभाग को 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।

इसमें से 15 करोड़ रुपए वितरित करने के बाद शेष 15 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए बिल तैयार किया जा रहा है। यह राशि ट्रेजरी ऑफिस के खाते में जमा करने के बाद वहां से बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। बता दें कि ईवी पॉलिसी को अगस्त 2022 में 5 साल के लिए लागू किया गया है।

ईवी खरीदने वाले को वाहन की कीमत का न्यूतम 10 फीसदी और अधिकतम 1.50 लाख रुपए सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लागू होने के बाद ईवी की जमकर खरीदी हुई। लेकिन, बजट नहीं होने के कारण पिछले 10 महीनों से ईवी खरीदारों को सब्सिडी का राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

खाते में रकम नहीं पहुंचने के कारण ईवी खरीदार बैंक, ऑटोमोबाइल डीलरों और आरटीओ के चक्कर लगा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजकर 70 करोड़ रुपए मांगे गए थे। साथ ही बताया गया था कि उनके पास केवल 70.05 लाख रुपए ही बचे है।

नए बजट से मध्यम वर्ग की उम्मीदें

डा. जयंती लाल भंडारी

ऐसे में देश में आयकर संग्रहण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आकार की तुलना में महज 11.7 फीसदी ही है, जबकि यह जर्मनी में 38 फीसदी, जापान में 31 फीसदी, ब्रिटेन में 25 फीसदी, अमेरिका में 25 फीसदी और चीन में 18 फीसदी है।

ऐसे में देश में आयकर संग्रहण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आकार की तुलना में महज 11.7 फीसदी ही है, जबकि यह जर्मनी में 38 फीसदी, जापान में 31 फीसदी, ब्रिटेन में 25 फीसदी, अमेरिका में 25 फीसदी और चीन में 18 फीसदी है। स्थिति यह है कि अमेरिका की 60 फीसदी और ब्रिटेन की 55 फीसदी आबादी आयकर चुकाती है। दुनिया की कई छोटी-छोटी अर्थव्यवस्थाओं में संग्रहित किए जाने वाले आयकर का उनकी जीडीपी में बड़ा योगदान है। अतएव हम उम्मीद करें कि इस बार वित्तमंत्री नए बजट से ऐसे लोगों को चिन्हित करने की नई रणनीति के साथ दिखाई देंगी, जिससे वास्तविक आमदनी का सही मूल्यांकन हो सके, लोगों के वित्तीय लेन-देन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही जो वास्तविक कमाई से कम पर आयकर देते हैं, उन्हें भी चिन्हित किया जा सके'...

इस समय पूरे देश की निगाहें 23 जुलाई को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2024-25 की ओर लगी हुई हैं। यह उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2012-13 के बाद महंगाई के हिसाब से जिस आयकरदाता और मध्यम वर्ग को राहत नहीं मिली है, अब वित्तमंत्री नए बजट के माध्यम से आयकरदाता और मध्यम वर्ग की क्रयशक्ति बढ़ाकर मांग में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को गतिशील करने की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकती हैं। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि मध्यम वर्ग को राहत देने को लेकर विशेष रूप से कोरोना महामारी के बाद लगातार मांग तेज हुई है। सरकार ने विगत वर्षों में जहां गरीब लोगों के लिए ढेर सारी राहतों का ऐलान किया,

वहीं कॉरपोरेट जगत पर भी सरकार ने ध्यान दिया। लेकिन राहत पाने के मद्देनजर सबसे अधिक टैक्स देने वाला मध्यम वर्ग पीछे छूट गया। 18वीं लोकसभा चुनाव के मतदान में मध्यम वर्ग की नाराजगी भी दिखाई दी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में कहा है कि मध्यम वर्ग देश के विकास का चालक है और मध्यम वर्ग कैसे कुछ बचत बढ़ा सके तथा मध्यम वर्ग के लोगों की जिंदगी को कैसे आसान बनाया जा सके, इस परिप्रेक्ष्य में रणनीतिकपूर्वक आगे बढ़ा जाएगा। गौरतलब है कि इस पूर्ण बजट 2024-25 के समय वित्तमंत्री सीतारमण के पास आयकर संबंधी मजबूत परिदृश्य मौजूद है।

पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में छलांगे लगाकर वृद्धि हुई है। 2023-24 में आयकर रिटर्न रिकॉर्ड 8 करोड़ के स्तर को पार कर चुका है और पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले दोगुने से अधिक हुए हैं। आयकर विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2013-14 में आयकर संग्रह करीब 2.38 लाख करोड़ रुपए था। यह फिर तेजी से बढ़ता गया। यह वर्ष 2019-20 में 10.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। कोरोनाकाल के कारण यह वर्ष 2020-21 में घटकर 9.47 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। यह वर्ष 2021-22 में 14.08 लाख करोड़ रुपए, वर्ष 2022-23 में 16.64 लाख करोड़ रुपए और वर्ष 2023-24 में 19.58 लाख करोड़ रुपए हो गया। ऐसे में वित्तमंत्री सीतारमण मजबूत वित्तीय मुट्ठी से आयकर के नए और पुराने दोनों स्लैब की व्यवस्थाओं के तहत करदाताओं व मध्यम वर्ग को अभूतपूर्व राहतों से लाभान्वित कर सकती हैं। खासतौर से वेतनभोगी वर्ग को लाभान्वित करने के भी विशेष प्रावधान नए बजट में दिखाई दे सकते हैं। इसके तहत मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) सीमा को 50000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए तक किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 में मानक कटौती की सीमा 40 हजार रुपए थी और वर्ष 2019 में इसे बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया था। नए बजट के तहत आयकर से संबंधित विभिन्न टैक्स छूटों में वृद्धि की जा सकती है। मौजूदा समय में धारा 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपए की छूट मिलती है। इसके तहत ईपीएफ, पीपीएफ, एनएससी, जीवन बीमा, बच्चों की ट्यूशन फीस और होम लोन का मूलधन भुगतान भी शामिल है।

मकानों की बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए धारा 80 सी के तहत 2.5 लाख से तीन लाख की छूट दी जा सकती है। इसी तरह सरकार के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 डी के तहत कर कटौती की सीमा को बढ़ा सकती है। ऐसे में सरकार के द्वारा 80 डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट को बढ़ा सकती है ताकि टैक्पेयर्स हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर प्रेरित हों। 80 डी में कर छूट सीमा को बढ़ाने के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सीमा बढ़ाई जाने से लोगों को स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) में योगदान की वार्षिक सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा सकता है। निःसंदेह देश में कर सुधारों से आयकर के संग्रहण में आशातीत वृद्धि हुई है। लेकिन अभी आयकर के कर दायरे में इजाफा किए जाने की बड़ी संभावनाएं हैं। जहां वर्ष 2024-25 के बजट से वित्तमंत्री आयकर राहत संबंधी उपहार सौंप सकती हैं, वहीं वे बजट में आयकर के दायरे का विस्तार करने की नई रणनीति का ऐलान कर सकती हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि बड़ी संख्या में उद्योग-कारोबार सेक्टर में कार्यरत रहते हुए कमाई करने वाले, महंगी आरामदायक व विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करने वाले, पर्यटन के लिए विदेश यात्राएं करने वालों में से बड़ी संख्या में लोग या तो आयकर न देने का प्रयास करते हैं या फिर बहुत कम आयकर देते हैं। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक पिछले एक वर्ष में करीब 24 लाख लोगों ने 10 लाख रुपए से महंगी कारें खरीदी, पिछले एक वर्ष में करीब 25 लाख लोगों ने 50 लाख रुपए से अधिक कीमत के महंगे घर खरीदे, वर्ष 2022 में देश के करीब 2.16 करोड़ लोगों ने पर्यटन के मद्देनजर विदेश यात्राएं की। इस तरह लोगों के पास पर्याप्त कमाई के कारण ही ये खरीदियां और विदेश यात्राएं संभव हैं।

लेकिन ऊंची कमाई करके भी बड़ी संख्या में लोग आयकर नहीं देना चाहते। वर्ष 2023-24 में देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों में से सिर्फ 2.79 करोड़ लोगों ने ही आयकर दिया है। यानी देश की आबादी के 1.97 फीसदी लोगों ने ही आयकर दिया है। ऐसे में आयकर का पूरा बोझ दो फीसदी से भी कम आबादी के द्वारा उठाया जा रहा है। साथ ही देश में कुल आयकर रिटर्न के करीब 70 फीसदी आयकर रिटर्न शून्य आयकर देयता बताते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में देश में आयकर संग्रहण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आकार की तुलना में महज 11.7 फीसदी ही है, जबकि यह जर्मनी में 38 फीसदी, जापान में 31 फीसदी, ब्रिटेन में 25 फीसदी, अमेरिका में 25 फीसदी और चीन में 18 फीसदी है। स्थिति यह है कि अमेरिका की 60 फीसदी और ब्रिटेन की 55 फीसदी आबादी आयकर चुकाती है। दुनिया की कई छोटी-छोटी अर्थव्यवस्थाओं में संग्रहित किए जाने वाले आयकर का उनकी जीडीपी में बड़ा योगदान है। अतएव हम उम्मीद करें कि इस बार वित्तमंत्री नए बजट से ऐसे लोगों को चिन्हित करने की नई रणनीति के साथ दिखाई देंगी, जिससे वास्तविक आमदनी का सही मूल्यांकन हो सके, लोगों के वित्तीय लेन-देन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही जो वास्तविक कमाई से कम पर आयकर देते हैं, उन्हें भी चिन्हित करके अपेक्षित आयकर चुकाने के लिए बाध्य किया जा सके। निश्चित रूप से इससे देश में टैक्स संग्रहण बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

संपादक की कलम से

पहाड़ी बोलियां खत्म हो जाएंगी

बोलियों में छुपा क्षेत्रवाद दाल माश को धाम में बांट देता है जहां, वहां राज्य की तासीर में टापुओं के धंसने का खतरा है बरकरार। जिस संस्कृति, बोली, भाषा, खान-पान, सादगी व पहाड़ीपन के साथ मिल कर हम एक हुए, हिमाचल की अस्मिता दिखी, वह अब भुरभुरा रहे अनेक टीलों पर सवार है। मराठी कलाकार के रूप में हिंदी के सुप्रिसद्ध एक्टर नाना पाटेकर को अगर अपने सुकून के लिए मराठी थियेटर और मराठी फिल्म में लौटना पड़ता है, तो इस सांस्कृतिक उजास को सलाम। महाराष्ट्र में कुल 38 जिले हैं और करीब इतनी ही बोलियां हैं जिनके सेतु पर मराठी भाषा का उद्भव, प्रभाव, साहित्य और संप्रेषण विकसित होता है। भले ही बालीवुड मुंबई को मुंबइया हिंदी भाषा देता है, लेकिन यह प्रदेश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मराठी की एकरूपता में सराबोर रखता है। इसी तरह गुजरात ने ग्यारह अलग-अलग बोलियों से गुजराती भाषा से जुड़ा एक प्रगतिशील भूगोल और भाषाई संबल चुन लिया। बांग्ला के उद्भव में प. बंगाल की पांच, तो मलयालम ने भी कमोबेश इतनी ही बोलियों के संगम पर केरल की अभिव्यक्ति को राष्ट्रीय फलक पर सजा दिया। हर राज्य ने बोलियों को विस्मृत होने से बचाने के लिए भाषाई संगठन से राज्य की भाषा का सांस्कृतिक चेहरा व ओज प्रकट किया। इसके विपरीत हिमाचली भाषा की जरूरत में क्षेत्रवाद के दर्पण टकराने लगते हैं और भय यह कि कहीं सियासत का यह दंभ टूट न जाए। यह इसलिए भी कि सृजन में पाखंड और ऐसे तत्वों का समावेश है जिनका दायरा दस से बीस किलोमीटर तक ही सिमट गया है। हिमाचल की आठ बोलियों से निकली सांस्कृतिक विरासत से अगर पंजाबी भाषा को संपन्नता मिलती है या जम्मू-कश्मीर की डोगरी में हिमाचल की दो से तीन बोलियां समाहित हैं, तो यह समझना होगा कि हिमाचली भाषा के कितनी नजदीक दो भाषाएं पहले ही समृद्ध हैं। स्वयं हिंदी भी, जिसे ओढक़र हिमाचल स्वयं को हिंदी राज्यों की श्रेणी में देखता है, अठारह बोलियों और पांव उप भाषाओं के गठजोड़ से पारंगत होती है। तेरह प्रमुख बोलियों और उप बोलियों के सामथ्य व समर्थन का सांस्कृतिक महत्त्व को स्वीकार करें तो जिस सेतु ने हिमाचल का अस्तित्व, पूर्ण राज्यत्व तथा सांस्कृतिक पहचान को जोड़ा, वही भावना एक हिमाचली भाषा में परिलक्षित हो रही है। अन्यथा जिन्हें बोली कह रहे हैं, उनके भीतर भी तो उप बोलियों की खाद जुड़ी है। मसलन कुल्लवी के भीतर सिराजी सैंजी और कुल्लवी का जिक्र अलग-अलग कर दिया जाए तो बचेगा क्या। शिमला में फिर क्योंथली, कोच्ची व बरारी में हम कितने जिले खोजेंगे, जबकि हकीकत में हमें हिंदी राज्यों के साथ नत्थी करके तत्कालीन मुख्यमंत्री शांता कुमार ने हिमाचल के भाषाई सरोकारों को चोट पहुंचा दी है। अब केवल तर्क के लिए भाषाई कोस मापे व कोष समझे जाते हैं, जबकि यथार्थ यह है कि आने वाली पीढियां धीरे-धीरे अपनी सांस्कृतिक विरासत का अर्थ भूल जाएंगी। हम हिमाचल के खान-पान में एक धाम को विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग बांट कर शौर्य अर्जित करना चाहते हैं, जबकि सीने पर फास्टफूड का कूड़ा लटका हुआ है। हिमाचल के स्वागत कक्ष में हर शहर में फूड चेन के बदलते नखरे, सांस्कृतिक समारोहों में बाहरी और खास तौर पर पंजाबी कलाकारों के साथ भांगड़े और प्रदेश के संबोधन में हिंदी व अंग्रेजी की जमात में पहुंचे हमारे अपने, स्पष्ट कर रहे हैं कि हिमाचली भाषा न बनी तो बोलियां भी शर्मिंदा हो कर मर जाएंगी। कोई हिमाचली भाषा होती तो हिमाचली थियेटर, हिमाचली साहित्य, हिमाचली विचार, हिमाचली दृष्टि और हिमाचली अभिव्यक्ति का अंदाज भी अपनत्व के साथ सभी कुछ अपना लेता। जरा सोचें बोलियों में हिमाचल का ठेठपन, उल्लास, व्यंग्य और परंपराएं अब हिंदी-अंग्रेजी के अक्स में दब गईं। हम प्रेम चंद तो बने नहीं, प्रताप चंद शर्मा भी नहीं रहे।

ज्ञान

सर्वर के सहारे दुनिया

विख्यात कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में क्या साइबर खामी आई कि लगभग दुनिया की सांसें हांफने लगीं। गतिविधियां थम गईं। अमरीका समेत जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सरीखे विकसित और प्रगतिवादी देशों में उड़ानें अवरुद्ध हो गईं अथवा रद्द करनी पड़ीं। उड़ानों के अलावा, बैंकिंग, रेलवे, स्टॉक एक्सचेंज, अस्पताल, रेस्तरां, डिजिटल पेमेंट्स, टीवी चैनलों से लेकर सुपर मार्केट सरीखी अत्यावश्यक सेवाएं ठहर गईं। कइयों को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट का यह एकाधिकार बेहद खतरनाक है। क्या इतने बड़े देशों के ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंपनी के सर्वर के भरोसे होने चाहिए? दुनिया के बड़े आर्थिक तंत्र के घटकों के लिए यह एक खास किस्म की विकलांगता है। दुनिया के 95 फीसदी से अधिक कम्प्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम से ही चलते हैं। उनका भरोसा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सिस्टम में कभी गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन सिर्फ एक खामी ने दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी को बेनकाब कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट को साइबर सुरक्षा देने वाली कंपनी-क्राउडस्ट्राइक-के अपडेट के कारण यह खामी पैदा हुई या पूरे सिस्टम में ही गड़बड़ी आई, लेकिन पूरी दुनिया सहम-सी गई, असमंजस में पड़ गई कि अब क्या किया जाए? ऐसे सर्वर की विश्वव्यापी सेवाएं देने वाली कंपनी के पास कमोबेश वैकल्पिक योजना होनी चाहिए थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने किसी 'प्लान बी' का इस्तेमाल नहीं किया। कंपनी सोचती रही कि साइबर सुरक्षा कंपनी क्राउडस्ट्राइक इस खामी को दुरुस्त करेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह एक ही सर्वर के भरोसे दुनिया चलाने की खतरनाक स्थिति है। ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट के विकल्प नहीं हैं। कई कंपनियां 'लाइनेक्स' और 'मेक' का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट का एकाधिकार है। चीन और रूस पर इस साइबर संकट का कोई भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने यह आशंका काफी पहले भांप ली थी, लिहाजा उन्होंने अपने-अपने सिस्टम को विकसित किया। उनके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, सर्वर हैं, वे पश्चिम के भरोसे नहीं हैं।

उनके पश्चिम के साथ संबंध भी बेहतर नहीं हैं। भारत को इस वैश्विक संकट से सबक सीखना चाहिए। हालांकि पहले दिन शुक्रवार, 19 जुलाई को दुनिया भर में 4295 हवाई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, लेकिन भारत में भी 200 उड़ानें रद्द की गईं। भारत की अधिकतर साइबर प्रणालियां माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से ही जुड़ी हैं। जरा कल्पना करें कि सर्वर फेल हो जाए और हमारा ऊर्जा-उत्पादन, थर्मल प्लांट, उड़ानें, मेट्रो समेत रेलवे सिस्टम, बैंकिंग और एटीएम, संचार, अस्पताल, डिजिटल लेन-देन आदि बुनियादी और अत्यावश्यक सेवाएं रुक जाएं, तो भारत ही ठप हो जाएगा! सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट और यूपीआई जैसे वित्तीय प्रौद्योगिकी सिस्टम बनाना हमारी क्षमताओं को बयां करते हैं। भारत चांद तक अपने अभियान की सफल यात्रा कर चुका है। हम 'आदित्य एल-1' अभियान के जरिए सूर्य का व्यापक अध्ययन कर रहे हैं। अंतरिक्ष में अनेक उपग्रह भेज चुके हैं। सॉफ्टवेयर के सर्वाधिक कुशल चेहरे हिंदुस्तान पैदा कर रहा है, जिनकी दुनिया भर में खूब मांग है। तो हम भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, पूरी तरह लागू क्यों नहीं कर सकते। इतनी संवेदनशील सेवाओं के लिए हम 'पराश्रित' क्यों हैं? अब कुछ सवाल हैं, जो आने वाले वक्त में स्पष्ट होंगे। मसलन-माइक्रोसॉफ्ट की ग्राहक कंपनियां अपने घाटे की भरपाई कैसे करती हैं? क्या मूल कंपनी उन्हें मुआवजा देगी? क्या इस तरह का कोई अनुबंध है?

कारगिल के योद्धाओं को याद करे राष्ट्र

भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के आगे पाक मिशन कोह-ए-पैमा पाक सेना के लिए इस कदर आत्मघाती साबित हुआ कि दुश्मन अपनी कयामत की दुआ मांगने पर मजबूर हो चुका था। कारगिल जंग में भारतीय शूरवीरों ने पाक सेना की तजवीज को नेस्तनाबूद किया'

भारतीय सेना 26 जुलाई को कारगिल युद्ध की पच्चीसवीं वर्षगांठ मनाएगी। यह दिन पाकिस्तान के लिए शर्मिंदा करने वाली तारीख है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को हथियाने के मंसूबे तैयार करता रहा है। मगर भारतीय सेना ने पाक हुक्मरानों की ख्वाहिशों का काफिला सरहद से आगे कभी नहीं बढने दिया। सन् 1980 के दशक में पाक सेना के कर्नल 'जावेद अब्बास' 'आफिसर कमांड एंड स्टाफ कालेज' 'क्वेटा' में सेवारत थे। जावेद अब्बास को पाक सेना ने भारत पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट 'इंडिया ए स्टडी इन प्रोफाइल' का काम सौंपा था। जावेद अब्बास ने अपने शोध में खुलासा किया था कि 'भारत के कुछ निजी मसलों का लाभ उठाकर हिंदोस्तान की ताकतवर सेना को कंट्रोल किया जा सकता है। सन् 1990 के दशक में पाक सेना के 'सैन्य अभियान महानिदेशक' के पद पर आसीन परवेज मुशर्रफ जावेद अब्बास के उस शोध से इस कदर प्रभावित हुए कि कश्मीर को हथियाने का जहालत भरा मंसूबा तैयार करने लगे तथा 'डीजीएमओ' रहते कश्मीर मंसूबे का मश्विरा पाकिस्तान की तत्कालीन वजीरे आजम बेनजीर भुट्टो के समक्ष पेश कर डाला। हालांकि परवेज मुशर्रफ के उस प्रस्ताव को मोहतरमा ने नाकाबिले अमल करार देकर खारिज कर दिया था, लेकिन वक्त ने करवट ली।

सन् 1998 में पाक वजीरे आजम नवाज शरीफ ने पाक सेना के दो सीनियर जरनैलों को दरकिनार करके परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान का चार सितारा जरनैल नियुक्त कर दिया। नवाज शरीफ की जिंदगी की यह सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 17 मई 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाक सेना के 'ओजड़ी कैंप' में वजीरे आजम नवाज शरीफ को कारगिल मंसूबे की ब्रीफिंग पेश करके कश्मीर का फातिम बनने का ख्वाब दिखाकर नियंत्रण रेखा के पार भारतीय हदूद में जाने की इजाजत लेने का ढोंग रचा था। जबकि हकीकत यह थी कि 18 हजार फीट की बुलंदी पर मौजूद कारगिल के दुर्गम क्षेत्रों में शीतकालीन स्थिति में भारतीय सेना जिन चौकियों को खाली कर देती थी, पाक सेना सन् 1999 के शुरुआती दौर में ही एलओसी पार करके उन चौकियों पर रक्षात्मक किलेबंदी कर चुकी थी। यानी पाकिस्तान 21 फरवरी 1999 के लाहौर समझौते को नजरअंदाज करके एलओसी पर मंसूंबाबंदी को अंजाम दे चुका था। उस पेशकदमी के दौरान एवलांच की चपेट में आने से कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत भी हो गई थी। एलओसी पर सिविल लिबास में घुसपैठ कर चुके हजारों सैनिक पाकिस्तान की 'नार्दर्न लाइट इन्फैंट्री' तथा 'स्पेशल सर्विस ग्रुप' के थे। कारगिल के मंसूबे को पाक सेना ने आपरेशन 'कोह-ए-पैमा' का नाम दिया था जिसका मकसद कारगिल क्षेत्र पर कब्जा करके सियाचिन ग्लेशियर को भारतीय सेना की पहुंच से अलग करके कश्मीर मसले को आलमी सतह पर दुनिया की निगाहों का मरकज बनाकर भारत पर रणनीतिक दबाव बनाना था। तीन मई 1999 को स्थानीय चरवाहों ने कारगिल क्षेत्र में पाक घुसपैठ की खबर भारतीय सेना को दी। छह मई 1999 को तुर्तुक क्षेत्र में 'जाट रेजिमेंट' की गश्त पार्टी पर पाक सेना की एनएलआई ने घात लगाकर हमला कर दिया। भीषण गोलीबारी में लांस नायक 'खडग़ सिंह गुर्जर' वीरगति को प्राप्त हो गए। खडग़ सिंह कारगिल युद्ध के प्रथम बलिदानी थे।

आठ मई 1999 को द्रास सेक्टर में भारतीय सेना की 'ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट' के चार जवान तथा 13 मई 1999 को 'गढ़वाल राइफल्स' की पैट्रोलिंग पार्टी के भी चार जवान पाक सेना से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। 14 मई 1999 को पाक घुसपैठ का पता लगाने के लिए कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में निकले गश्ती दल का कॉकसर क्षेत्र में पाक सेना से मुकाबला हुआ। सौरभ कालिया का गश्ती दल दुश्मन से आखिरी गोली तक लड़ा, मगर गोला बारूद खत्म होने के बाद उस गश्ती दल को हिरासत में लेकर पाक सेना ने उन सैनिकों की नृशंस हत्या कर दी थी। सौरभ कालिया के गश्ती दल को खोजने के लिए उनकी यूनिट 'चार जाट' का एक अन्य गश्ती दल 17 मई 1999 को कैप्टन अमित भारद्वाज के नेतृत्व में निकला। मगर पाक सेना से मुठभेड़ के दौरान कैप्टन अमित भारद्वाज सहित तीन अन्य जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उन शहीद सैनिकों के पार्थिव शव सीजफायर के बाद 56 दिनों के बाद उठाए गए थे। कारगिल के पहाड़ों पर पाकिस्तानी घुसपैठ का पर्दाफाश होने के बाद 19 मई तक कारगिल सेक्टर युद्ध क्षेत्र घोषित हो चुका था। भारतीय सेना ने 'आपरेशन विजय' लांच करके जब पूरी तजवीज से पलटवार किया तो कारगिल का महाज पाक सेना के लिए कयामत का मंजर पेश करने लगा। बटालिक सेक्टर में 17 हजार फीट की बुलंदी पर प्वांइट 5203 पर कब्जा जमा चुकी पाक फौज पर '12 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फैंट्री' के कैप्टन अमोल कालिया ने अपने सैन्य दल के साथ आठ जून 1999 को जोरदार हमला करके उस क्षेत्र को मुक्त कराने में अहम किरदार निभाया था, मगर आक्रामक कार्रवाई के दौरान अमोल कालिया अपने कई सैनिकों के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए थे।

दुश्मन की भीषण गोलीबारी के कारण अमोल कालिया का पार्थिव शव भी बारह दिनों बाद 20 जून 1999 को बरामद किया गया था। युद्ध में उत्कृष्ट बहादुरी के लिए सेना ने हिमाचली शूरवीर कै. अमोल कालिया को 'वीर चक्र' (मरणोपरांत) से नवाजा था। 'खालूबार' पर्वतीय श्रेणी पर स्थित प्वांइट 4812 पर भी '12 जैकलाई' के सात जवानों ने शहादत को गले लगाकर तीन जुलाई 1999 को कब्जा जमाया था तथा कारगिल जंग के जिंदा सबूत पाकिस्तानी सैनिक 'इनायत अली' को हिरासत में लिया था। भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के आगे पाक मिशन कोह-ए-पैमा पाक सेना के लिए इस कदर आत्मघाती साबित हुआ कि दुश्मन अपनी कयामत की दुआ मांगने पर मजबूर हो चुका था। बहरहाल कारगिल जंग में भारतीय शूरवीरों ने पाक सेना की तजवीज को नेस्तनाबूद करके पाकिस्तान के नामुराद जरनैलों की कश्मीर फतह करने की जंगी सनक को ध्वस्त कर दिया था। लाजिमी है विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्र कारगिल के योद्धाओं की दास्तान-ए-सुजात को नमन करे। देश अपने रणबांकुरों के शौर्य का हमेशा ऋणी रहेगा।

शव संवाद-53

भूख को मारने निकला बुद्धिजीवी उस दिन हैरान हो गया कि दुनिया में कई लोगों को मालूम ही नहीं कि वे भी भूखे हैं। जनता की भूख में वे भूख के लिए, भूख के साथ सदा दृढ़ रहे हैं। उन्हें यह भी पता नहीं कि अति भूख भी एक तरह की तरक्की है। भूख के लक्षण अब पेट में कहां होते, यह तो एक तरह की उपलब्धि है जो सफल लोगों की तुलना गरीबों से करती है। सरकारों ने भूख को तकिया कलाम बना लिया, वरना इसे कब से मिटाया जा सकता था, बल्कि किसी राशन डिपो को देखकर तो कतई नहीं लगता कि इसे खत्म करना संभव है। बुद्धिजीवी भिखारी के पास पहुंच गया। उसने लाख कोशिश की कि उसके भीतर भूख मार दे, लेकिन वह हर बार इसी स्थिति में मिल जाता है। भूख के पास खड़ा वह प्रोफेशनल लगने लगा है। भूखे न होते तो कौन लंगर के प्रोफेशन में आता। लोग बंदरों को भूखा समझते हुए ढेर लगा देते हैं। दो बंदर आपस में बतिया रहे थे, 'बड़े भाई! यह दाना, ब्रेड और चने डालने वाले क्या हमें भूखा समझते हैं या भूखा बनाने के लिए अपनी क्षमता दिखा रहे हैं।' दूसरा बंदर ब्रेड खाते हुए बोला, 'भूख तब होती है जब स्वाद नहीं होता, यानी जब पशुओं का खाना इनसान खा लेता है और सुना है लोग चारा भी खा लेते हैं, क्योंकि भूख होती है। हम भूख नहीं जानते, और न ही भूख से कोई गिला है।' एक दिन बुद्धिजीवी को साक्षात भूख मिल गई। वह अपनी ही लाज में लिपटी, सकुचाई हुई, उससे आंखें चुराने लगी, बल्कि कुछ समय तक तो उसे विश्वास भी नहीं हुआ कि भूख ऐसी भी हो सकती है। इतनी सुधरी हुई तथा सुंदर। यह चुनावी भूख थी। इसके ऊपर सभी पार्टियों की नजर थी। भूख जान बचा कर भाग कर आई थी। उसे मालूम था कि चुनाव में हर दल अपनी महत्त्वाकांक्षा में उसके पीछे पड़ा है।

भूख के नशे में राजनीति है, जबकि भूख खुद हमेशा सदाचारी, ब्रह्मचारी और कभी-कभी कर्मचारी हो जाती है। भूख सेकुलर है। आज तक कोई धर्म नहीं अपनाया। वरना इसकी भूख से दूसरा धर्म नाराज हो जाता या भूख का अपना कोई धर्म बन जाता। न भूख ने और न ही भिखारी ने आज तक कोई दंगा किया, बल्कि खाए-पीए लोग ही इस विधा के माहिर रहे। खैर बुद्धिजीवी को यकीन था कि भूख हमेशा एक ही पोज में रहती है। भूख के न हाथ हैं और न ही पांव। न वह काम करती और न ही चल सकती। न बचपन, न जवानी, फिर भी एक दिन उसने अपने भीतर से भरी हुई भूख को बाहर निकलते देखा। यह वह भूख थी जो उसके बुद्धिजीवी बनते ही मर गई थी। लाश की तरह भूख ने बुद्धिजीवी को कहा, 'तुम कितने निर्दयी हो। बरसों से मुझे दबोच रखा है। पहले मुझे पढ़ाते रहे, फिर सपने दिखाते रहे। आखिर मुझे छुपाकर तुझे क्या मिला, सिर्फ यही कि दुनिया ने तुझे कभी भूखा नहीं माना। फिर भी मेरी कहानी तुम्हारे साथ यही है कि मैं हर बार तेरे पास आकर ही मरी।' बुद्धिजीवी अपनी मरी हुई भूख को सहला रहा था कि सामने कोई इश्तहार फेंक गया। मरी हुई भूख को ढांप रहा इश्तहार बता रहा था कि तुरंत निवेश करके वह अपनी बचत को दोगुना कर लेगा। भूख की लाश उसे रोक रही थी, लेकिन बुद्धिजीवी ने जीवन की सारी कमाई निवेश में लगा दी। बिना भूख के वह अपनी दौलत फिर हार चुका था। आखिर बुद्धिजीवी था हर काम पढ़ कर ही करता था।

F&O ट्रेडिंग पर आर्थिक सर्वे ने जताई चिंता, क्या बजट में होगा टैक्स बढ़ाने का एलान?

परिवहन विशेष न्यूज

इकोनॉमिक सर्वे ने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में खुदरा निवेशकों के बढ़ते पार्टिसिपेशन पर चिंता जताई है। सर्वे के मुताबिक इस तरह स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की भारत जैसे विकासशील देश में कोई जगह नहीं। इसमें आगाह किया गया है कि शेयर बाजारों में किसी भी संभावित गिरावट से निवेशक ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं। फिर हो सकता है कि वे लंबे समय तक शेयर बाजार में न लौटे।

नई दिल्ली। आर्थिक सर्वे में शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के प्रति चिंता जाहिर की गई। सर्वे में कहा गया है कि बाजार की स्थितियों को जांचें-परखें बिना ऊंचे रिटर्न की उम्मीद करना चिंता का विषय है। हालांकि इसी के साथ सर्वे में यह भी कहा गया है कि खुदरा निवेशकों की बढ़ी हुई हिस्सेदारी पूंजी बाजार को स्थिरता प्रदान करती है।

पिछले कुछ सालों के दौरान अपने खुदरा निवेशकों ने अपने खाते से पूंजी बाजार में सीधी खरीदारी की या म्यूचुअल फंड के माध्यम से बड़ी मात्रा में परोक्ष खरीदारी की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, 'इक्विटी कैश सेगमेंट टर्नओवर में खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी 2023-24 (वित्त वर्ष 24) में 35.9 प्रतिशत थी। दोनों डिपॉजिटरी (एनएसई और बीएसई) के पास डीमैट खातों की संख्या वित्त वर्ष 2022-23 में 11.45 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 15.14 करोड़ हो गई।

20 फीसदी परिवार की घरेलू बचत शेयर बाजार में

बाजार में निवेशकों की इस आमद का असर एक्सचेंजों के साथ नए निवेशक पंजीकरण, कुल कारोबार मूल्य में उनकी हिस्सेदारी, शुद्ध निवेश में भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, एनएसई में पंजीकृत निवेशकों की संख्या मार्च 2020 से लगभग तीन गुना बढ़कर 31 मार्च, 2024 तक 9.2 करोड़ हो गई है। इसका सीधी मतलब यह है कि अब 20 प्रतिशत भारतीय परिवार अपनी घरेलू बचत को वित्तीय बाजार में लगा रहे हैं।

शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की होने वाली वृद्धि पर सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अति आत्मविश्वास के चलते अधिक रिटर्न की उम्मीद करना बाजार परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकती है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है।

निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री

डेरिवेटिव के खिलाफ लोगों को जागरूक करें डेरिवेटिव बाजार में खुदरा निवेशकों की रुचि को देखते हुए सर्वे में कहा गया है, "डेरिवेटिव हे¨जग इंस्ट्रूमेंट है। इसका उपयोग दुनियाभर के निवेशकों द्वारा सट्टा इंस्ट्रूमेंट के रूप में किया जाता है। भारत संभवतः इसका अपवाद नहीं है।' सर्वेक्षण में कहा गया है, "डेरिवेटिव ट्रे¨डग में बहुत अधिक लाभ की संभावना है। इस तरह यह लोगों को जुआ खेलने की प्रवृत्ति की ओर उकसाता है।" सर्वे में डेरिवेटिव के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया गया है।

वृद्धि गाथा में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं पूंजी बाजार

पूंजी बाजारों की देश की वृद्धि की गाथा में अब प्रमुख भूमिका बनती जा रही है। संसद में सोमवार को पेश 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में यह बात कही गई है। समीक्षा में कहा गया कि नवोन्मेष और डिजिटलीकरण के दम पर पूंजी निर्माण और निवेश परि²श्य में बढ़ती हिस्सेदारी के साथ पूंजी बाजार देश की वृद्धि गाथा में अपनी भूमिका बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आज भारतीय बाजार वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक झटकों को झेलने में अधिक सक्षम हैं।

आर्थिक समीक्षा कहती है कि बढ़ते

भू-राजनीतिक जोखिम, बढ़ती ब्याज दरों और ¨जस कीमतों में अस्थिरता के बावजूद भारतीय पूंजी बाजार का प्रदर्शन बीते वित्त वर्ष में अन्य उभरते बाजारों में सबसे बेहतर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में बीएसई का 30 शेयर वाला सूचकांक सेंसेक्स करीब 25 प्रतिशत चढ़ा। चालू वित्त वर्ष में भी यही रुख जारी है और तीन जुलाई को सेंसेक्स दिन में कारोबार के दौरान पहली बार 80,000 अंक के स्तर को छू गया।

म्यूचुअल फंड के लिए शानदार रहा वित्त वर्ष 2024 वित्त वर्ष 2024 के अंत में उनके प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) में 14 लाख करोड़ रुपये या 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 53.4 लाख करोड़ रुपये हो गई। वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में 14.6 करोड़ से वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में फोलियो की कुल संख्या बढ़कर 17.8 करोड़ हो गई।

किसने पेश किया था भारत का पहला बजट, कैसे बना था इनकम टैक्स स्लैब?

परिवहन विशेष न्यूज

1857 के क्रांतिकारी विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को बड़े पैमाने पर धन-बल का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे ब्रिटिश हुकूमत का खजाना तकरीबन खाली हो गया। अंग्रेजों ने जनता की नाराजगी कम करने और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए भारत का अलग से बजट पेश करने का फैसला किया। इसके लिए एक बड़े अर्थशास्त्री को बुलाया गया जो थे जेम्स विल्सन (James Wilson)।

नई दिल्ली। साल 1857 की क्रांति कई मायनों में ऐतिहासिक थी। यह पहली दफा था, जब देशभर के क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा। यह विद्रोह बेशक असफल रहा, लेकिन इसके कई दूरगामी प्रभाव हुए। उन्हीं में से एक था, भारत का अपना बजट और इनकम टैक्स स्लैब।

क्यों पड़ी बजट की जरूरत?

1857 के गदर को दबाने के लिए अंग्रेजों को बड़े पैमाने पर धन-बल का इस्तेमाल करना पड़ा। इसका बोझ सरकारी खजाने पर भी पड़ा। ब्रिटिश हुकूमत ने जनता की नाराजगी कम करने और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए भारत का अलग से बजट पेश करने का फैसला किया। इसके लिए एक बड़े अर्थशास्त्री को बुलाया गया, जो थे जेम्स विल्सन (James Wilson)।

कौन थे जेम्स विल्सन?

जेम्स विल्सन स्कॉटिश व्यापारी और मशहूर अर्थशास्त्री थे। 3 जून 1805 को जन्मे जेम्स के पुरखे भेड़पालन करते थे। उनके पिता का टोपियां बनाने का कारखाना था। जेम्स ने ही 'द इकोनॉमिस्ट' की नींव रखी थी, जो आज भी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस मैगजीन समझी जाती है। उन्होंने ही 'चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना' की स्थापना की थी।

जेम्स विल्सन मुक्त व्यापार के हिमायती थी। जर्मन दार्शनिक और अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स (Karl Marx) भी जेम्स को तमाम अर्थशास्त्रियों के बीच बड़ा ऊंचा दर्जा देते थे। जेम्स को 1857 की क्रांति के बाद भेजा गया और वह इंडियन काउंसिल के वित्त सदस्य बने। उनका काम भारत के वायसराय को मशविरा देना था, जिसके हाथ में उस समय देश की कमान होती थी।

कब पेश हुआ पहला बजट?

1857 विद्रोह के बाद भारत की शासन प्रणाली में आमूलचूल बदलाव हुए। ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय प्रशासन की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी से खुद ले ली। इसका मतलब कि भारत का प्रशासन पूरी तरह से ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। उन्होंने 7 अप्रैल, 1860 को पहली बार भारत का बजट पेश करवाया और बजट पेश करने वाले शख्स थे, पहले फाइनेंस मेंबर जेम्स विल्सन।

विल्सन ने क्या 'सुधार' किए?

यह विडियो भी देखें

इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य ने अपनी किताब- द फाइनेंशियल फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश राज में लिखा है कि ब्रिटिश हुकूमत डायरेक्ट टैक्स लागू करने पर विचार कर रही थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ऐसे में उनकी मुश्किल आसान की जेम्स विल्सन ने। विल्सन ने दो नए विधेयक पेश किए, आयकर और लाइसेंस कर। जेम्स विल्सन ने एलान किया कि 200 रुपये से कम सालाना आय वाले लोगों को टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी।

इनकम टैक्स की शुरुआत के बाद काफी विवाद खड़ा हो गया। खासकर, जमींदारों और व्यापारियों को इस पर एतराज था। हालांकि, विल्सन ने दलील दी कि ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों को व्यापार का सुरक्षित माहौल दे रही है और उसके बदले में टैक्स बस मामूली सी फीस है। जेम्स विल्सन ने मासिक व्यय खातों की निगरानी के लिए अंग्रेजी मॉडल पर आधारित विनियोग लेखा परीक्षा भी शुरू की। उन्होंने देश में कागज की करेंसी का चलन भी शुरू किया।

कौशल विकास के माध्यम से रोजगार, दिशा सही, मंजिल अभी दूर

रोजगार और कौशल विकास को प्राथमिकता पर रखते हुए सरकार ने इशारा कर दिया कि मोदी 3.0 कार्यकाल में इस क्षेत्र के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले जा सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार की ओर से दावा किया गया है कि 2017-18 से 2022-23 की अवधि में ग्रामीण शहरी और महिला-पुरुष यानी लिंग वर्गीकरण सहित सामाजिक-आर्थिक वर्गीकरण में कुशल श्रम बल के अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

नई दिल्ली। कौशल विकास के लिए मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से चल रहे प्रयासों के परिणाम इतना तो आश्वस्त करते हैं कि प्रयास सही दिशा में हैं, लेकिन सरकार के ही आंकड़े यह स्थिति भी स्पष्ट करते हैं कि मंजिल अभी बहुत दूर है। आर्थिक सर्वेक्षण में श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट-2022-23 के हवाले से बताया गया है कि 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के मात्र 4.4 प्रतिशत युवाओं ने ही औपचारिक रूप से व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि अन्य 16.6 प्रतिशत ने अनौपचारिक माध्यम से प्रशिक्षण लिया है।

रोजगार और कौशल विकास को प्राथमिकता पर रखते हुए सरकार ने इशारा कर दिया है कि मोदी 3.0 कार्यकाल में इस क्षेत्र के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले जा सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार की ओर से दावा किया गया है कि 2017-18 से 2022-23 की अवधि में ग्रामीण, शहरी और महिला-पुरुष यानी लिंग वर्गीकरण सहित सामाजिक-आर्थिक वर्गीकरण में कुशल श्रम बल के अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

मसलन, 2017-18 में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 2.5 प्रतिशत युवा कुशल श्रेणी में थे, जबकि 2022-23 में यह आंकड़ा 4.4 प्रतिशत हो गया। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में इसी समयावधि में यह आंकड़ा 1.7 से बढ़कर 3.4 प्रतिशत, शहरी में 4.4 से वृद्धि कर 7.2 प्रतिशत हो गया। कुशल महिलाओं के आंकड़े में लगभग दोगुणी वृद्धि हुई है। यह 2.2 से बढ़कर 4.2 प्रतिशत पर पहुंच गया है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के आंकड़े प्रदर्शित करते हुए सरकार ने यह भी बताया है कि पिछले बजट में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की थी।

वाराणसी और भुवनेश्वर में केंद्र शुरू कर दिए गए हैं। बाकी के लिए स्थानों का चयन हो चुका है और पहले चरण के तहत जल्द ही सात नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने संभावनाओं के साथ चुनौतियों की ओर भी इंगित किया है। जैसे कि स्किल गैप को कम करने में शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रमों यानी इंटर्नशिप को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन शिक्षा जगत और उद्योग के बीच समन्वय की कमी है। बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं है।

इन्फ्रा विकास में निजी क्षेत्र का भी साथ जरूरी

सर्वेक्षण के अनुसार कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले दस वर्षों में बड़े पैमाने पर काम हुआ है दोनों सेक्टरों की मांग है कि भूमि अधिग्रहण में देरी से निपटने के लिए सुधारवादी कदम उठाए जाएं। जमीन से संबंधित मंजूरियां जल्दी मिलनी चाहिए। लैंड रिकार्ड को डिजिटल बनाने की रफ्तार भी धीमी है। शासन के हर स्तर पर इस समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएं।

नई दिल्ली। देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे के विकास की रफ्तार तो तेज है, लेकिन इस ढांचे को गुणवत्तापूर्ण और विशेष रूप से विश्वस्तरीय बनाने के लिए निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ना चाहिए। सरकार को नए स्त्रोतों से संसाधन जुटाने होंगे और उन्हें एकजुट करना होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में बुनियादी ढांचे की तस्वीर बताते हुए एक बार फिर यह रेखांकित किया गया है कि इस क्षेत्र के विकास में जो चीजें आड़े आ रही हैं, उनमें भूमि अधिग्रहण में दिक्कतें सबसे ऊपर हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले दस वर्षों में बड़े पैमाने पर काम हुआ है, लेकिन दोनों सेक्टरों की मांग है कि भूमि अधिग्रहण में देरी से निपटने के लिए सुधारवादी कदम उठाए जाएं। जमीन से संबंधित मंजूरियां जल्दी मिलनी चाहिए। लैंड रिकार्ड को डिजिटल बनाने की रफ्तार भी धीमी है। शासन के हर स्तर पर इस समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। हवाई अड्डों के विकास के मामले में समय बहुत महत्व रखता है, जगह के चयन को लेकर भी विकल्प सीमित होते हैं।

ऐसे में जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होना जरूरी है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 से 2023 के बीच इन्फ्रा विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से 49 और राज्य सरकारों की ओर से 29 प्रतिशत पैसा खर्च किया गया। निजी क्षेत्र का योगदान केवल 22 प्रतिशत रहा।

क्या स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से MSP देना मुमकिन है? कांग्रेस सरकार ने क्यों किया था खारिज

परिवहन विशेष न्यूज

किसान लंबे समय से मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इस मांग को लेकर लंबे समय तक धरना प्रदर्शन भी किया। विपक्षी दल भी किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार एमएसपी की गारंटी देने का समर्थन करते हैं। हालांकि कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस फार्मूले पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) देना संभव नहीं है।

नई दिल्ली। स्वामीनाथन आयोग ने सी-2 फार्मूले के आधार पर खेती की लागत में 50 प्रतिशत राशि जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने की सिफारिश की थी। इसमें संसाधन, श्रम, समग्र पूंजी एवं जमीन की टेनेंसी रेट को भी शामिल करने की बात कही गई है।

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस फार्मूले पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) देना संभव नहीं है, क्योंकि विभिन्न राज्यों की जमीन का भाव अलग है। लीज रेंट अलग है। यहां तक कि एक ही गांव के विभिन्न हिस्से के भूखंड के दाम भी एक नहीं है। ऐसे में लागत के आकलन का कोई एक आधार नहीं हो सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व में बनी केंद्र की पूर्व सरकार का भी ऐसा ही मानना था।

क्या थी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश

स्वामीनाथन आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 में किया गया था। आयोग ने किसानों के कल्याण के लिए कुल पांच रिपोर्ट सौंपी। अंतिम रिपोर्ट चार अक्टूबर 2006 में सौंपी

गई, जिसमें कहा गया कि एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होनी चाहिए।

कांग्रेस सरकार ने सिफारिश लागू क्यों नहीं की?

आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। केंद्र ने आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया। यहां तक कि तत्कालीन कृषि मंत्री केवी थामस ने सदन में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को अगर लागू कर दिया जाएगा तो बाजार में तबाही आ जाएगी। यह भी कहा कि एमएसपी और उत्पादन लागत को तकनीकी तौर पर जोड़ना उल्टा भी पड़ सकता है।

अभी 24 फसलों पर मिल रही है MSP

केंद्र सरकार अभी 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। इसका निर्धारण केंद्र सरकार राज्यों एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है। उत्पादन की लागत, मांग-आपूर्ति की स्थिति, कीमतों का रुझान, कृषि व्यापार की शर्तें, उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था पर एमएसपी के प्रभाव के साथ भूमि एवं पानी जैसे संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग जैसे कारकों पर विचार के बाद एमएसपी का निर्धारण किया जाता है।

शहरीकरण की रफ्तार तेज, राज्यों और निकायों को आना होगा आगे

संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार शहरीकरण की इस रफ्तार से निपटने के लिए केंद्र सरकार राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को मिलकर शहरी ढांचा बनाना होगा। बुनियादी ढांचे के विकास के संदर्भ में सरकार ने मुख्य चुनौतियों में यह भी रेखांकित किया है कि अलग-अलत स्तरों पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी एक समग्र तस्वीर उपलब्ध नहीं है।

नई दिल्ली। शहरीकरण की रफ्तार में तेजी का आलम यह है कि अगले पांच-छह साल में 40 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरों में रह रही होगी, लेकिन इससे जुड़ी चुनौतियां भी गंभीर हैं। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार शहरीकरण की इस रफ्तार से निपटने के लिए केंद्र सरकार, राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को मिलकर शहरी ढांचा बनाना होगा। तभी शहर विकास के आर्थिक केंद्रों के रूप में उभर सकेंगे।

प्रभावशाली प्लानिंग की जरूरत

यह उद्देश्य हासिल करने के लिए शहरी क्षेत्रों की प्रभावशाली प्लानिंग, परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सशक्त तंत्र और शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना जरूरी है। केंद्र सरकार की यह भी राय है कि शहरी विकास से संबंधित परियोजनाओं पर क्रियान्वयन के दौरान शहरी स्थानीय निकायों और एजेंसियों को पैसे के सही इस्तेमाल को लेकर व्यापक विश्लेषण करना होगा। बुनियादी ढांचे के विकास के संदर्भ में सरकार ने मुख्य चुनौतियों में यह भी रेखांकित किया है कि अलग-अलत स्तरों पर जो पैसा खर्च हो रहा है, उसकी एक समग्र तस्वीर उपलब्ध नहीं है।

रिपोर्टिंग के कई फार्मेट हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को सेक्टर आधारित आवंटन के लिए विस्तृत सूचना की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए शहरों की आर्थिक स्थिति जानने-समझने के लिए शहरी कार्य मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस पोर्टल बनाया है, लेकिन उसमें सारी स्थिति बताने के मामले में निकायों का रवैया ढीला-ढाला है। इस पोर्टल से सेक्टर आधारित पूंजीगत खर्च का ब्यौरा जान पाना आसान नहीं है।

फंसी आवासीय परियोजनाएं बड़ी चुनौती

आर्थिक सर्वेक्षण में रियल इस्टेट सेक्टर के लिए उत्साहजनक तस्वीर है, क्योंकि तेज शहरीकरण के साथ घरों की मांग भी तेज रहने के आसार हैं, लेकिन अलग-अलग कारणों से फंसकर ठप पड़ गईं आवासीय परियोजनाओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। लगभग 4.1 लाख ऐसे घरों का निर्माण वर्षों से रुका हुआ है, जिसमें चार लाख

करोड़ रुपय से अधिक की पूंजी फंसी हुई है। इनमें से लगभग सवा दो लाख घर तो केवल एनसीआर में हैं।

नई नीतियों और रणनीति की जरूरत

केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने सभी पक्षों-सरकार, विकास प्राधिकरण, बैंकों, डेवलपरों और घर खरीदने वालों से समस्या का समाधान करने के लिए कुछ नुकसान सहने की अपेक्षा की थी। सर्वे में इस पर जोर दिया गया है कि घरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई नीतियों और रणनीति की जरूरत है जिससे व्यावहारिक, कम लागत वाले और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल घरों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा सके। सर्वे के अनुसार दो साल कोविड महामारी के प्रकोप के चलते ठप हो गए रियल एस्टेट सेक्टर ने पिछले दो सालों में वापसी कर ली है।

पिछले सालों में हुई बढ़ोत्तरी

सर्वे के अनुसार जिन कारणों से रियल इस्टेट सेक्टर के लिए उत्साहजनक तस्वीर बनी है, उनमें तीव्र शहरीकरण, लोगों की बढ़ती आमदनी, एकल परिवारों का बढ़ता चलन, बाजार में बढ़ता मुकाबला और डेवलपरों तथा घर खरीदारों के लिए बेहतर वित्तीय विकल्प शामिल हैं। सर्वेक्षण में एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि 2013 के बाद पिछले साल आवासों की बिक्री सबसे अधिक रही है। आठ बड़े शहरों में 4.1 लाख घरों की बिक्री हुई है और वार्षिक वृद्धि 33 प्रतिशत रही है।

हमारे जीवन में कंप्यूटर शिक्षा का महत्व

विजय गर्ग

कंप्यूटर शिक्षा क्या है ? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग किसी समस्या को हल करने या दिए गए निर्देशों के अनुसार एक निश्चित कार्य करने के लिए किया जा सकता है। आज लगभग हर जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर शिक्षा कंप्यूटर के बारे में सीखने या सिखाने की प्रक्रिया है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम का बुनियादी ज्ञान, कौशल, विचार और कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित बुनियादी शब्दावली शामिल हैं। इसमें कंप्यूटर के फायदे और नुकसान, कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता, दैनिक जीवन की विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जा सकता है या चरम समस्या को हल करने के लिए कंप्यूटर को कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है, यह भी शामिल है। कंप्यूटर शिक्षा इक्कीसवीं सदी का एक अभिन्न अंग बन गई है। आज के जीवन में इसका बहुत महत्व हो गया है। आज लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसलिए कंप्यूटर के बारे में सीखना जरूरी हो गया है. हमारे जीवन में कंप्यूटर शिक्षा का महत्व कंप्यूटर छात्रों को दुनिया के बारे में जानने और यह जानने में मदद करता है कि इसमें क्या हो रहा है। इससे उन्हें भविष्य में उत्कृष्ट नौकरियों का लक्ष्य रखने और उसमें सफल होने में मदद मिलती है। कंप्यूटर दुनिया भर में शिक्षा का एक मानक बन गया है। यह कंप्यूटर शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाता है। कंप्यूटर शिक्षा के कुछ महत्व इस प्रकार हैं: कंप्यूटर शिक्षा अनुसंधान कौशल में सुधार करती है: एक कंप्यूटर आज के जीवन में अनुसंधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है जो कि इंटरनेट है। इंटरनेट को एक ऐसे नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विभिन्न नेटवर्कों को जोड़कर बनाया जाता है। आज इंटरनेट लगभग किसी भी चीज़ में हमारी मदद कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेट हमें शोध में मदद करता है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से लेकर प्रयोगशालाओं में काम करने वाले वैज्ञानिक तक, कंप्यूटर, या यूं कहें कि इंटरनेट, हर किसी को शोध में मदद करता है। इंटरनेट लगभग उन सभी विषयों पर प्रचुर जानकारी से भरा पड़ा है जिनके बारे में हम जानते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में छात्रों को उन विषयों पर शोध करने या प्रोजेक्ट बनाने के लिए कुछ छुट्टियों का होमवर्क दिया जाता है जिनके बारे में वे नहीं जानते हैं। इन विषयों में, जिनके बारे में छात्रों को कोई जानकारी नहीं है, इंटरनेट उनकी मदद करता है। इंटरनेट उन्हें

आवश्यक विषय पर बहुत सारी जानकारी दे सकता है। एक वैज्ञानिक पहले से मौजूद खोजों को खोजकर नई खोज करने के लिए इंटरनेट की मदद ले सकता है। इसलिए कंप्यूटर रिसर्च में बहुत मदद कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर के बारे में जानकारी आवश्यक है। हर किसी को पता होना चाहिए कि अपने स्वयं के अनुसंधान कौशल को बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और उससे जुड़े संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए। कंप्यूटर शिक्षा अच्छी नौकरियाँ पाने में मदद करती है: आज कंप्यूटर उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कंप्यूटर की जरूरत हर जगह होती है. वे प्रत्येक उद्योग का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं। आज लगभग हर काम कंप्यूटर पर निर्भर है। इसलिए उद्योग या कंपनियाँ उन श्रमिकों को काम पर रखती हैं जो कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित हैं या जिनके पास कंप्यूटर का उपयोग करने का कुछ ज्ञान है। विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही कंप्यूटर शिक्षा सिखाई जानी चाहिए। उन्हें कंप्यूटर के क्षेत्र में अच्छी पकड़ हासिल करनी चाहिए। विद्यार्थी को अपने पूरे शैक्षणिक जीवन में कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में इतना प्रशिक्षित हो जाना चाहिए कि हर कंपनी उसे नौकरी पर रखे। तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो लोग अच्छी नौकरी की इच्छा रखते हैं, उनके लिए कंप्यूटर शिक्षा बहुत जरूरी है। जिन लोगों को कंप्यूटर सिस्टम का पूरा ज्ञान है, उन्हें दिया जाने वाला वेतन पैकेज उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक है, जिन्हें कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कंप्यूटर शिक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ाने में मदद करती है:आज अधिकतर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सिस्टम पर निर्भर करती है। बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर खगोलीय उपकरणों तक, हर चीज़ के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर कोई नई तकनीक बनाना चाहता है तो उसे कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति एक ऐसी मशीन बनाना चाहता है जिसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जा सके। परिणाम तैयार करने के लिए मशीन को कुछ उपकरण की आवश्यकता होगी। यह डिवाइस एक कंप्यूटर सिस्टम का संशोधित संस्करण है। इसलिए व्यक्ति को कंप्यूटर को संशोधित करने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षित होना चाहिए। जब कोई

व्यक्ति कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करता है, तो वह नई तकनीकें बनाने के लिए प्रेरित महसूस करता है। यह उनके दिमाग को कुछ नई तकनीक बनाने के लिए नए विचारों से भर देता है जिसका उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर शिक्षा व्यक्ति की कार्यकुशलता को बढ़ाती है: ऐसे व्यक्ति पर विचार करें जिसे कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं है। वह व्यक्ति किसी कंपनी के अकाउंट विभाग में काम करता है। व्यक्ति को कंपनी के सभी वित्तीय रिकॉर्ड का ध्यान रखना होता है, उसे शुरुआत से ही कंपनी के सभी लाभ और हानि का रिकॉर्ड बनाए रखना होता है। इसके लिए बहुत अधिक समय, एकाग्रता, गति और स्मृति की आवश्यकता होगी। ये बहुत मुश्किल काम है. यह कार्य व्यक्ति के लिए बहुत थका देने वाला होता है क्योंकि सभी रिकॉर्ड कलम और कागज का उपयोग करके तैयार करना पड़ता है। दूसरी ओर, ऐसे व्यक्ति पर विचार करें जिसे कंप्यूटर सिस्टम का ज्ञान हो। वह कंपनी के सभी खातों को बनाए रखने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करेगा। उन्हें रिकॉर्ड बनाए रखने में कम समय लगेगा क्योंकि उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली हर चीज़ कंप्यूटरीकृत हो जाएगी। उसे अपने रिकॉर्ड संग्रहीत करने के लिए किसी भौतिक स्थान की आवश्यकता नहीं होगी जिसकी आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो कंप्यूटर नहीं जानता है। इसमें कम समय लगेगा. किये गये कार्य तेजी से होंगे। दोनों मामलों की तुलना करने पर, कंप्यूटर जानने वाले व्यक्ति की दक्षता कंप्यूटर नहीं जानने वाले व्यक्ति से अधिक होगी। इसलिए कंप्यूटर शिक्षा का होना जरूरी हो जाता है। कंप्यूटर शिक्षा एक बेहतर शिक्षा वातावरण बनाने में मदद करती है: इन दिनों स्मार्ट क्लासरूम उभर रहे हैं। प्रत्येक स्कूल अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। यह अधिक प्रभावी सीखने और सिखाने का माहौल बनाता है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से सीखना आसान हो जाता है। यह आसान होने के साथ-साथ और भी मजेदार हो जाता है। स्मार्ट कक्षा में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा आवश्यक है। प्रत्येक स्कूल उन शिक्षकों को नियुक्त करना पसंद करता है जो कंप्यूटर को शिक्षण उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग बहुत सी चीजें सिखाने के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीमीडिया उपलब्ध होने से कठिन विषयों को आसानी से समझा जा सकता है। कम्प्यूटरीकृत माध्यम से छात्रों को दी गई जानकारी नियमित जानकारी की तुलना में उनके द्वारा अधिक आसानी से रखी जाती है। इसलिए छात्रों को उचित और प्रभावी शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षकों को कंप्यूटर प्रणाली और उनके उपयोग के बारे में उचित शिक्षा होनी चाहिए। कंप्यूटर शिक्षा संचार को आसान बनाती है: दुनिया बहुत बड़ी है। हमारे सभी प्रियजन हमारे साथ नहीं रहते। हम सभी अपने प्रियजनों के साथ संवाद करना चाहते हैं जो दुनिया या देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। पत्र से शुरू हुआ संवाद टेलीफोन तक आ गया। पत्र बहुत लंबी दूरी तक प्रभावी संचार प्रदान नहीं करते थे और संचार केवल पाठ-आधारित था। टेलीफोनिक बातचीत एक कदम आगे थी। हम अपने प्रियजनों की आवाज़ सुन सकते थे। आज की तकनीक में हम संचार के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। यह हमें जैसी सुविधाएँ प्रदान करता हैई चैटिंग, कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संचार में काफी मदद मिली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या हम कह सकते हैं कि वीडियो चैट या वीडियो कॉलिंग का फीचर आजकल खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे हमें उस व्यक्ति को देखने में मदद मिलती है जिससे हम बात कर रहे हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो गया है जो अपने परिवारों से बहुत दूर रहते हैं क्योंकि अब वे उनके साथ संवाद कर सकते हैं जैसे वे उनके सामने बैठे हों। कंप्यूटर का उपयोग करके संचार की इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता होती है। आजकल, जो बच्चे अपने माता-पिता से दूर रहते हैं वे अपने माता-पिता को संचार के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना सिखा रहे हैं ताकि वे उनके साथ आसान और सस्ता संचार कर सकें।

टैक्स के आधार पर बुजुर्ग व्यापारियों को पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए : अध्यक्ष राजेश खुराना

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा। केंद्र सरकार 23 जुलाई को बजट 2024-25 पेश करेगी और इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आर्थिक सर्वेक्षण संसद के पटल पर पेश कर दिया है। इसमें प्राइवेट सेक्टर पर सरकार का विशेष फोकस नजर आया है। वहीं, इस बजट में एक अहम विषय टैक्स में बदलाव को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है।

इस सन्दर्भ में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश खुराना ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार का पहला बजट पेश होने जा रहा है। केंद्र सरकार 23 जुलाई यानी कल मंगलवार को बजट 2024-25 पेश करेगी। इस बजट से आगरा के जूता उद्योग को भी जीएसटी में राहत की काफ़ी उम्मीद है। कल पेश होने वाले बजट से जूता कारोबारी आशान्वित हैं। हमें सरकार से उम्मीद है कि टैक्स घटाने से जूता उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि व्यापारियों की मांगों पर वित्तमंत्री विचार करेंगी और इसीलिए जनपद के व्यापारियों की नजर 2024 के बजट पर लगी है। व्यापारियों ने जीएसटी में छूट की मांग की है।

श्री खुराना ने आगे कहा कि दुनिया भर में आगरा यहां बनने बाले जूते के लिए अलग पहचान रखता है। आगरा के जूते से कोई भी पैर अछूता नहीं है। आगरा

जनपद के प्रमुख जूता कारोबार से 3.50 लाख से अधिक परिवार जुड़े हैं। यहां से दुनिया भर में नूते का निर्यात होता है। वहीं, दुनिया में 68 फीसदी जूते की आपूर्ति आगरा से होती है। जूता पर अभी 12 फीसदी जीएसटी है। अगर सरकार जूता कारोबार पर पूर्व की घटाकर तरह 5 फीसदी जीएसटी कर देती है तो इससे व्यापारियों को बड़ी सुविधा और राहत मिलेगी तथा व्यापार बढ़ेगा और रोजगार सृजन भी होगा और टैक्स कम होने से जूता उद्योग और ऊंचाइयों को छू सकेगा। उन्होंने कहा कि टैक्स के आधार पर 60 साल से अधिक उम्र के व्यापारियों को पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए और सरकार को 60 साल से अधिक उम्र के व्यापारियों को आयकर में भी छूट मिलनी चाहिए।

भारत के युवाओं का डिगता भरोसा : विजय गर्ग

हमें गर्व है कि हम एक युवा देश हैं, क्योंकि हमारी आधी से अधिक आबादी छत्तीस वर्ष तक की उम्र के युवाओं की है। उसमें से भी तीन-चौथाई आबादी ऐसे नौजवानों की है, जो सोलह से छब्बीस वर्ष की उम्र के हैं और अपने लिए इस नए भारत में जिंदगी की सार्थकता तलाश रहे हैं। इस नाराप्रेमी और उत्सवधर्मी देश में नौजवान अपने लिए अपनी जमीन और थोड़े से आत्मगौरव की तलाश करते हैं। उन्हें अनुकंपाओं की बरसात से भीगी धरती की जगह धूप से तपती मेहनत मांगती वह धरती चाहिए, जो उनकी योग्यता के अनुसार रोजी-रोजगार दे सके और वे अपनी मेहनत से सफलता की की सीढ़ियां चढ़ते हुए, बिना किसी बैसाखी के जी सकें। मगर ऐसा नहीं है।

नवनिर्माण और नवजागरण के लिए सबसे पहले तो शिक्षा और सम्माजनक पेशे चाहिए। इनके लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जो उनकी योग्यता का उचित मूल्यांकन करके उन्हें सम्मानजनक रोजगार दे सकें। मगर रोजगार की गारंटी इस देश में नहीं है। जो नौजवान जय जवान, जय किसान और जय अनुसंधान के देश को दिए मूलमंत्र का अनुसरण करते हुए अपनी जमीन की तलाश करना चाहते हैं, उन्हें उचित प्रशिक्षण के लिए दाखिला परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। पिछले दशकों में ऐसे शिक्षण संस्थान निजी क्षेत्र में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए हैं। शिक्षा दुकान न बने, उसके दाखिले चोर दरवाजे न बनें, इसके लिए देश में एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की स्थापना की गई। फैसला किया गया कि नौजवान अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रतिष्ठानों की परीक्षाएं देने को न भटकते फिरें। उन्हें एक देश, एक परीक्षा का मूलमंत्र एनटीए द्वारा दे दिया गया। अब चिकित्सक बनना है। या 'उसमें विशिष्टता हासिल करनी है, इंजीनियर या प्राध्यापक बनना या शोध छात्र, इन सबके लिए परीक्षाएं एनटीए के झंडे तले आयोजित होती हैं। वर्ष में ऐसी लगभग पंद्रह परीक्षाएं एनटीए आयोजित करता है और उनमें अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए करीब दो करोड़ विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठते हैं।

मगर इस प्रक्रिया में हर वर्ष पर्चाफोड़ होते हैं। इस वर्ष भी यही हुआ। इस पुरानी बीमारी का इलाज क्यों नहीं हो पाता ? क्या इसलिए कि इसकी परीक्षा एजेंसी को कोई नियमित सुदृढ़ ढांचा देने के बजाय 'जैसा है, उसे निभाओ' का नियम दे दिया गया। एजेंसी में पंद्रह शीर्ष लोग तो अलग-अलग प्रतिनियुक्ति से आ गए, पर ,पर परीक्षाएं अंततः निजी एजेंसियों को ठेके पर दी जाने लगीं। जाहिर है, ऐसे माहौल में पर्चाफोड़ से लेकर अन्य भ्रष्ट तरीकों की कितनी संभावनाएं रहेंगी। इसकी चरम सीमा शायद इस बार हो गई, जब 571 शहरों के 4750 परीक्षा केंद्रों में 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने एमबीबीएस दाखिले के लिए 'नीट' परीक्षा दी। नतीजा निकला तो 67 छात्र प्रथम श्रेणी थे, उन्हें 720 में से 720 अंक मिले। स्पष्ट हुआ कि नंबरों का बंटवारा तर्कहीन तरीक से हुआ है। शोर- शराबा हो गया। जांच में पता चला कि सीमित ढंग से अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया गया। पकड़ धकड़ होने लगी। बिहार से बहुत-सी खबरें आईं, लेकिन परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले।

इस बार की गड़बड़ी से परीक्षार्थियों का विश्वास परीक्षा लेने वाली एजेंसियों पर से डिग गया है। योग्यता का मूल्यांकन अगर इसी तरीके से होना है कि परीक्षा के ढांचे में चोर गलियां निकल आएंगी और अयोग्य छात्र उन्हें धक्का देकर निकल जाएंगे, तो इससे बड़ा अन्याय उन मेहनती छात्रों के लिए क्या हो सकता था, जो वर्षों से घर छोड़कर कोटा जैसी जगहों में परीक्षाओं की तैयारी करने में दिन-रात एक कर रहे थे। परीक्षाएं तो सही मूल्यांकन के विश्वास के आधार पर चलती हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट ने भी 18 जून को नीट मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि 0.001 फीसद भी गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच करो। सीबीआइ की जांच में यहां-वहां दोषी भी पकड़े जाने लगे । संसद में इस पर बहस की मांग उठी।

नौजवान ही किसी देश का भविष्य होते हैं और जब वही अंधेरे में भटकने लगें, तो देश का भविष्य भला कैसा होगा ? सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं पर विचार हुआ कि क्या 'नीट' की दुबारा परीक्षा ली जाए ? परीक्षा में भ्रष्ट तरीकों और पर्चाफोड़ की पुष्टि हो गई। मगर जवाबी याचिका भी आ गई कि उन लाखों विद्यार्थियों का क्या दोष, जिन्होंने पूरी मेहनत से इम्तिहान दिए और अब उन्हें फिर उसी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहा जा रहा है। जबकि हर पढ़ने वाला जानता है कि उसी उत्साह के साथ बार-बार परीक्षाओं की तैयारी नहीं हो सकती। खैर, मामला सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में है। केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे भी सुप्रीम कोर्ट में आए हैं कि 'नीट' परीक्षा दुबारा करने की जरूरत नहीं। लाखों मेहनती छात्रों को दुबारा बेवजह परीक्षा की भट्टी में न झोंका जाए। दोषी तो पकड़े जाएं, लेकिन 'नीट' के यही परीक्षा परिणाम सफल छात्रों के साथ रहेंगे, देशभर की चिकित्सा संस्थाओं में दाखिले के लिए।

इन इम्तिहानों के आधार पर अलग-अलग मेडिकल कालेजों में काउंसिलिंग शुरू होने लगी थी, जो अब जुलाई के अंत तक टल गई और सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसले का इंतजार हो रहा है। फैसला जो भी हो, सवाल इस समस्या के फौरी हल का नहीं है। वह तो हो ही जाएगा। सवाल यह है कि मेहनती युवा पीढ़ी को उनकी मेहनत का उचित मूल्यांकन कैसे होना है, इसका स्थायी हल कैसे निकाला जाए ? कुछ बातें बहुत स्पष्ट हैं। योग्य व्यक्तियों का स्थायी ढांचा बनना चाहिए, जो ये परीक्षाएं करवाएं और देशभर में इतने महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए स्थायी परीक्षा मशीनरी बने, जिसकी कार्यशीलता और इमानदारी पर कोई भी व्यक्ति अंगुली न उठा सके। जब तक यह नहीं होगा, तब तक नौजवानों का विश्वास, जो अपने भविष्य के प्रति पहले ही शंकालु हैं, अपनी परीक्षाओं के प्रति भी अनिश्चय के भंवर में फंसा रहेगा।

हम शिक्षा की खामियों को करने की बात कहते हैं। नए-नए शिक्षा माडल दे रहे हैं, लेकिन इसके एक जरूरी हिस्से यानी छात्र ने जो पढ़ा, उसका सही मूल्यांकन करके उसे रोजी-रोजगार देने के बारे में अभी तक सही फैसले नहीं हो सके। ये फैसले तत्काल होने चाहिए। देश के नव-निर्माण की बात करने वाले पहले देश की युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा के नए ढांचे के निर्माण को तुरंत बनाना शुरू करें। तदर्थ उपायों से काम नहीं चलेगा। शिक्षा आपके अंतस को जगाती है। छात्र की योग्यता का तटस्थ मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा विशारदों को तैयार रहना चाहिए। यह ठेका परीक्षा प्रणाली नहीं चलेगी। देश के शिक्षा प्रवीण सिर जोड़कर बैठें और ऐसा वैकल्पिक ढांचा बनाएं, जिसमें देश के युवा छात्र अपने विश्वास और सहज माहौल के साथ यहां अपनी योग्यता को प्रस्तुत कर सकें। इस योग्यता का सही मूल्यांकन होगा, इसका विश्वास उन्हें रहे। तभी देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना उनमें जागेगी।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब

गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल एवं अन्य विरासत के पतन के लिए नेता जिम्मेदार

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। दिल्ली के प्रमुख सिखों ने गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों जैसी विरासत सामुदायिक संस्थाओं के पतन के लिए भ्रष्ट नेताओं को जवाबदेह ठहराने की कसम खाई है ।इस संबंध में बैठक की मेज़बानी करने वाले पंथक नेता हरविंदर सिंह सरना ने कहा, "हम अपने एक समय के गौरवशाली शैक्षणिक संस्थानों की अवनति के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तलाश करेंगे। हमारा लक्ष्य फंड जुटाने और गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों जैसी विरासत संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए भ्रष्ट नेताओं की संपत्तियों की नीलामी करना है।"

नई दिल्ली के एक होटल में आयोजित बैठक में सरदार अमरजीत सिंह चंढोक, उद्योगपति सरदार हरदीप सिंह बंगा, सरदार मनजीत सिंह जीके (पूर्व अध्यक्ष डीएसजीएमसी), सरदार करतार सिंह चावला, सरदार जतिंदर सिंह साहनी (महासचिव शिरोमणि अकाली दल, दिल्ली इकाई), सरदार कुलतरान सिंह कोछड़, सरदार तजिंदर सिंह गोपा, सरदार जितेंद्र सिंह सोनू, सरदार अमरीक सिंह विकासपुरी, सरदार सतनाम सिंह खालसा, सरदार सुरिंदर सिंह दारा, सरदार मोहिंदर सिंह, डॉ. परमिंदर पाल सिंह एमएन, सरदार दर्शन सिंह, सरदार मनजीत सिंह सरना, युवा नेता सरदार रमणदीप सिंह सोनू, सरदार एच. पी. सिंह, सरदार रमणदीप सिंह क्वात्रा और मीडिया पी आर ओ भूपेंद्र सिंह वअन्य प्रमुख सिख हस्तियाँ शामिल थीं।

"सिख शैक्षणिक संस्थानों का पुनरुद्धार हमारा प्रमुख मिशन है। हमारे सामूहिक प्रयास किसी भी व्यक्ति के लिए जो व्यक्तिगत लाभ के लिए इन संस्थानों को नष्ट करने की कोशिश करेगा, एक निवारक के रूप में कार्य करेंगे," सरना ने कहा।बैठक के समापन पर दिल्ली अकाली दल के प्रमुख और पूर्व डीएसजीएमसी अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

ज़िला कलेक्टर ने किया ज़िले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण

समयबद्ध रूप से कार्यालयों में लगातार अनुपस्थित रहने पर की जाएगी सख़्त कार्रवाई

पीएचईडी कार्यालय में गंदगी पाई जाने पर ज़िला कलेक्टर ने जताई नाराज़गी , स्वच्छता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

परिवहन विशेष अनुप कुमार शर्मा

शाहपुरा। ज़िले में कार्यालय निर्धारित समय से पहुँचने के अनुशासन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को ज़िला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने ज़िले में संचालित हो रहे विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। ज़िला कलेक्टर शेखावत द्वारा ज़िले के पीएचईडी कार्यालय तथा एविएनएल कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ज़िला कलेक्टर शेखावत ने पीएचईडी तथा एविएनएल कार्यालय के प्रत्येक सेक्शन की कार्यप्रणाली का मुआइना किया तथा सभी लंबित प्रकरणों के समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियो तथा कर्मचारियो को निर्देशित किया। शेखावत ने पीएचईडी कार्यालय के प्रांगण में साफ़सफ़ाई दुरुस्त ना पाए जाने पर नाराज़गी जताते हुए वहाँ

मौजूद अधिकारियो तथा कर्मचारियो को कार्यालय में व्यवस्थित रूप से साफ़ सफ़ाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

ज़िला कलेक्टर शेखावत ने बताया की कार्य संचालन में समयबद्धता के अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा इस प्रकार के आकस्मिक निरीक्षण भविष्य में भी किए जाएँगे तथा लगातार अधिकारियो एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यालय समय पर कार्यालय में अनुपस्थित पाये जाने तथा कार्यालयों में व्यवस्थित साफ़ सफ़ाई सुनिश्चित ना करने पर सख़्त कार्रेवाई की जाएगी।

शिक्षा मंत्री दिलावर ने किया वर्च्युअल तो विधायक प्रतिनिधि सेन ने रिबन काट किया अनुशरण

मॉडल स्कूल बागोर में विधिवत हुआ प्राथमिक कक्षाओं का शुभारम्भ।

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। बागोर राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के तहत व सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अगुवाई में आज प्रदेशभर में

134 मॉडल विद्यालयों में प्राइमरी सेटअप का वर्च्युअल शुभारंभ किया गया। ठीक इसी शुभारंभ के चलते बागोर पुरोहित खेड़ा रोड़ स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बागोर ब्लॉक माँण्डल में आज सत्र 2024-25 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओ का शुभारम्भ क्षेत्रीय विधायक उदय लाल भडाणा के प्रतिनिधि लाल चंद सेन के कर कमलों द्वारा किया गया I इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक प्रतिनिधि लाल चंद सेन ने रिबन काट कर नवनिर्मित भवन का अवलोकन करते हुए कक्षा 1 से 5 तक कि कक्षाओं का संचालन भी प्रारम्भ करवाया I

मॉडल स्कूल के प्रवेश प्रभारी डॉक्टर अनुज नुवाल ने बताया कि सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 5 तक प्रवेश हेतु पंजीयन फॉर्म 5 जुलाई से 12 जुलाई के मध्य विद्यालय समय में आवेदन आमंत्रित किये जाकर उनका नियमानुसार प्रवेश पॉलिसी के तहत प्रवेश कार्य को पूर्ण किया गया था I वही कक्षा 1 से 5 तक में कुल 200 बच्चों की सीटें हैं जिनमें प्रति कक्षा 40 सीट निर्धारित हैं। जिसमें छात्राओं कि 22 तथा छात्रों कि 18 सीट निर्धारित हैं।

शुभारम्भ के इस कार्यक्रम के अवसर पर विधायक प्रतिनिधि लाल चंद सेन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए विद्यालय प्रशाशन को आश्वासित किया कि विद्यालय के शैक्षणिक एवं भौतिक विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा एवं राज्य सरकार से हर संभव मदद भी दिलवाई जाएगी I इनके साथ ही मण्डल अध्यक्ष हेमेन्द्र सिंह राणावत, रामराय सेठिया व खूबी राम सेठिया ने भी अपने अपने विचार व्यक्त कर छात्र छात्राओं को मार्गदर्शित किया I वही विद्यालय प्रधानाचार्य एजाज़ हुसैन शेख ने सभी आगुन्तको का अभिनंदन कर आभार प्रकट किया और साथ ही नवप्रवेशित छात्र छात्राओ का पुष्पमाला पहना स्वागत सत्कार कर प्रवेशोत्सव मनाते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि विद्यालय प्रशाशन एवं स्टॉफ द्वारा उनकी शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखते हुए सर्वांगीण विकास भी किया जाएगाI

इस कार्यक्रम का संचालन कीर्ति परिहार ने किया और कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का धन्यवाद भी ज्ञापित किया I

शुभारंभ के इस अवसर पर बागोर भाजपा मण्डल अध्यक्ष हेमेन्द्र सिंह राणावत, पूर्व मण्डल अध्यक्ष श्रवण सिंह चूंडावत, राम राय सेठिया, खूबी राम सेठिया, हरिकिशन बसवाल, राकेश सेन, नानूराम माली, कैलाश चंद सेवक, शांति लाल आचार्य, राधेश्याम खटीक, राधेश्याम आचार्य, भीमराज वैष्णव, लक्ष्मी लाल ओझा सहित बागोर के कई गणमान्य नागरिक व अभिभावक मौजूद थे ।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023